

हजारीबाग जेल से फरार तीनों कैदी महाराष्ट्र से हुए गिरफ्तार

तकनीकी साक्ष्यों व खुफिया इनपुट से मिली सफलता, अलग-अलग रास्तों से भागे थे अपराधी

PHOTON NEWS HAZARIBAG : लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से 31 दिसंबर को रात डेढ़ बजे फरार हुए तीन कैदियों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की विशेष टीम ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों फरार कैदियों को दबोच लिया। लंबे समय से चल रही तलाश के बाद मिली इस सफलता को पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, वहीं जेल सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवालोंने के बीच यह कार्रवाई अहम मानी जा रही है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए कैदियों की पहचान देवा भुइयां, जितेंद्र रवानी और राहुल पंजवार के रूप में हुई है। तीनों



पुलिस गिरफ्तार में आरोपी व जानकारी देते एसीपी अंजनी अंजन

ईट मद्रा में कर रहे थे मजदूरी

एसीपी ने बताया कि फरारी के बाद तीनों कैदी अलग-अलग तरीके से निकले और बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र के सोलापुर जिला पहुंचे। ये वहां करमाला थाना क्षेत्र में ईट-भट्टे में मजदूरी कर रहे थे और मजदूरों के बीच ही छिपकर रहे थे। इन्हें पकड़ने के लिए एक टीम तकनीकी शाखा के सहयोग से काम कर रही थी, दूसरी टीम कैदियों के संभावित मूवमेंट का ट्रैक खगाल रही थी, जबकि तीसरी टीम लगातार विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही थी।

आरोपी पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद थे और बैरक नंबर-6 में एक साथ रखे गए थे। देवा भुइयां करीब नौ महीने से जेपी केंद्रीय कारा में बंद था, जबकि जितेंद्र रवानी और राहुल पंजवार को लगभग तीन महीने पहले ही जेल भेजा गया था। जेल में सामने आया है कि तीनों कैदियों ने फरारी की पूरी योजना

पहले से तैयार कर रखी थी। जेल में सोने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चादरों को आपस में जोड़कर उन्होंने एक अस्थायी रस्सी बनाई। इसी रस्सी के सहारे रात के अंधेरे में जेल की ऊंची दीवार फांदकर तीनों कैदी फरार हो गए। इस घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर

जिले में छिपे हुए हैं। इसके बाद हजारीबाग पुलिस की टीम ने सोलापुर जिले के करमाला थाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापेमारी की और तीनों फरार कैदियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह ऑपरेशन पूरी तरह गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया, ताकि आरोपी देवाभागे में सफल न हो सकें। तीनों आरोपियों को ट्रॉजिंट रिमांड पर हजारीबाग लाया गया है। पुलिस का कहना है कि कैदियों को सूछताह के बाद फरारी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जाएगी। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इस घटना में जेल के अंदर से किसी प्रकार की लापरवाही या मिलीभगत तो नहीं हुई।



पुलिस गिरफ्तार में नक्सली

रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार नक्सली झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बहुलानिया गांव का निवासी है। गया जिले में कई नक्सली वारदातों को अंजाम देने के बाद वह लंबे समय से अपने गांव में ही छिपकर रह रहा था। छापेमारी के दौरान जैसे ही पुलिस टीम बहुलानिया गांव पहुंची, छोटू रविदास ने भागने की कोशिश की। हालांकि, पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के बाद त्वरित रणनीति बनाते हुए एक संयुक्त टीम को झारखंड

कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभियान को पूरी तरह गोपनीय रखा गया था, ताकि नक्सली को फरार होने का मौका न मिल सके। **कई गंभीर मामलों में वाछित :** छोटू रविदास उर्फ शिवनंदन रविदास के खिलाफ गया जिले के डुमरिया थाना में नक्सली गतिविधियों से जुड़े कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, बम विस्फोट, हथियारों का इस्तेमाल और नक्सली संगठन के लिए काम करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।

BRIEF NEWS

गायत्री परिवार के शिविर में 205 यूनिट रक्तदान



JAMSHEDPUR : अखिल विश्व गायत्री परिवार नवयुग दल युवा प्रकोष्ठ एवं प्रज्ञा महिला मंडल द्वारा काशीडीह स्थित डीएसएम स्कूल फॉर एम्सीलेंस में रविवार को शिविर लगाया गया, जिसमें 205 यूनिट रक्तदान हुआ। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर गायत्री परिवार द्वारा यह रक्तदान शिविर पूरे राज्य के 19 जिलों में आयोजित किया गया था। शिविर का उद्घाटन भाजपा नेता अभय सिंह, एस्पी इंटर कॉलेज-परसुडीह के पूर्व प्रचार्य प्रो. एचपी शुक्ला, व गायत्री शक्तिपीठ टाटनगर के दिनेश सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इनके साथ मांगों के पोस्टमास्टर रोहित माशॉल सुरेन, गायत्री परिवार के शंभुनाथ दुबे, राजन गुप्ता व रक्तदान अभियान के संयोजक संजीव सिन्हा भी उपस्थित थे। आयोजकों ने बताया कि यह रक्तदान शिविर गायत्री परिवार की वरिष्ठ कार्यकर्ता रहीं प्रज्ञा महिला मंडल की स्व. गिरिजा दुबे की पुण्य स्मृति में भी समर्पित किया गया।

अवैध कोयला खदानों में डोजरिंग, माफिया में हड़कंप



DUMKA : जिले के गोपीकांदर अंचल क्षेत्र के ओडमो गांव में अवैध तरीके से संचालित कोयला खदानों में एक बार फिर से डोजरिंग रविवार को किया गया। डोजरिंग के दौरान सीओ विजय प्रकाश मरांडी, थाना प्रभारी सुमित कुमार भगत, खनन निरीक्षक गोख दुबे, मनजीत सिंह सहित काठीकुंड रेंज के रेंजर एलआर रवि शामिल थे। डोजरिंग से पूर्व वन उपरिसर पदाधिकारी सुबेन हांसदा ने माइक में आवाज देकर लोगों को सतर्क किया। उन्होंने बताया कि यदि कोयला खान के अंदर कोई व्यक्ति हो बाहर निकल जाए, डोजरिंग करने के बाद यदि कोई ऐसे स्थिति आती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी वह व्यक्ति खुद होगा। डोजरिंग में लगे तीन जेसीबी मशीनों ने दो खदानों को पूरी तरह मिट्टी भरकर बंद कर दिया। कोयला खदान तक जाने वाली रास्ते को भी जेसीबी मशीन से गड्डे खोदकर बंद कर दिया गया है। अवैध रूप से संचालित कोयला खदानों में डोजरिंग को लेकर बड़ी संख्या में महिला और पुरुष पुलिस बल की तैनाती की गई थी। ओडमो में अवैध कोयला खदानों में यह चौथी बार डोजरिंग किया गया। इससे पूर्व डीएमओ दिलीप कुमार तांती और कृष्ण कुमार किन्कू के कार्यकाल में तीन दफा डोजरिंग हो चुकी है। इस दौरान एएसआई धर्मल मांझी, वन विभाग के साकेत कश्यप, अरुण कुमार, दुगापूर के वन उपरिसर पदाधिकारी सुबेन हांसदा, खनन विभाग शंकर मंडल सहित पुलिस बल मौजूद थे।

डाल्टनगंज-रांची मुख्य पथ पर सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, दो घायल

शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे तीनों, ओवरस्टेक करने में चली गई जान

PHOTON NEWS PALAMU : नेशनल हाईवे-39 डाल्टनगंज रांची मुख्य पथ पर सतबरवा थाना क्षेत्र के खामडीह में बंगला स्कूल के पास रविवार को हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक दोस्त की शादी का कार्ड बांटने के लिए अपने अन्य दो दोस्तों के साथ निकला था। वहीं इस घटना में दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए एमएससीएच, मेदिनीनगर में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान अंजय उरांव के रूप में हुई है। वह कुलिया गांव का रहने वाला था। जख्मी युवकों में अंशु उरांव और पंकज उरांव शामिल हैं। अंशु की शादी 20



अस्पताल में इलाजगत घायल

फरवरी को होने वाली थी। तीनों दोस्त उसकी बहन के घर रजडेवरा कार्ड बांटने जा रहे थे। तीनों एक साथ मजदूरी करते थे

रजडेवरा गांव जाने के लिए निकले थे। खामडीह में बंगला स्कूल के पास एक वाहन को ओवरस्टेक करने के बाद सामने से आ रहे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। ग्रामीणों से इस घटना की जानकारी मिलने पर सतबरवा थाना की पेट्रोलिंग गश्ती में शामिल एएसआई सुखसागर सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और तीनों को बाइक को इलाज के लिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां एक को मृत पाया गया। इलाज के बाद भी दोनों घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर, चर्चा है कि तीनों युवकों ने रास्ते में शराब का सेवन किया था।

नशा नहीं हो सकता तनाव या दबाव का हल : प्रधान जिला जज

LATEHAR : नालसा एवं झालसा के निदेशानुसार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार शेषनाथ सिंह के मार्गदर्शन में रविवार को विधिक सेवा प्राधिकार लातेहार द्वारा व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। मीडिया के माध्यम से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार शेषनाथ सिंह ने कहा कि नशा कुछ पत्तों का भ्रम देता है, लेकिन आपको मेहनत और लक्ष्य आपको स्थायी सफलता दिलाएगा। कहा कि मानसिक शक्ति को पहचानें, तनाव या दबाव का हल नशा नहीं है। अपनी समस्याओं को साझा करें और योग या खेल जैसी सकरात्मक गतिविधियों से खुद को जोड़ें। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति अभियान के साथ जुड़कर स्वस्थ जीवन की शुरुआत करें। सिंह ने युवाओं को संदेश दिया कि एक-दूसरे के सच्चे दोस्त बनें, अगर आपका कोई दोस्त नशे की राह पर है, तो उसे रोके और सही राह दिखाएं। इस अभियान-जीवन को हां कहे- नशे को ना कहे- के तहत समाज में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस अभियान के अंतर्गत सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय मीडिया का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। अभियान के उद्देश्य को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्टर, वीडियो और इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से महत्वपूर्ण संदेशों का प्रसार किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके। इसके साथ ही वाट्सएप ग्रुप और विभिन्न वेबसाइटों के माध्यम से जागरूकता संबंधी संदेश साझा किए जा रहे हैं।



अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार

मेधा डेयरी का प्लांट मानगो से सरायकेला स्थानांतरित, आक्रोश

JAMSHEDPUR : झारखंड सरकार की मेधा दूध डेयरी का प्लांट मानगो से सरायकेला स्थानांतरित हो गया है। इसे लेकर मानगो में बालीगुमा सुखना बस्ती के लोगों को बड़ा झटका लगा है। लंबे समय से जिस 50 टीएलपीडी मेधा डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट के लगने की उम्मीद में ग्रामीण अपने क्षेत्र के विकास और रोजगार के सपने देख रहे थे, वह अब मानगो में नहीं बनेगा। राज्य सरकार ने इस प्लांट को सरायकेला-खरसावां जिले के तित्तिरबिला गांव स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है, जिस पर तब शुक्रवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में अंतिम मुहर लगा दी गई। इस फैसले से सुखना बस्ती के ग्रामीणों में निराशा और आक्रोश दोनों साफ दिखाई दे रहे हैं। एक दशक से अधिक समय से लोग इस परियोजना के जरिए रोजगार के अवसर, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और क्षेत्र के समग्र विकास की आस लगाए बैठे थे, लेकिन अब यह सपना टूटता नजर आ रहा है। प्लांट के स्थानांतरण की खबर मिलते ही स्थानीय लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

दो बाइकों की टक्कर में युवक की मौत, 4 घायल

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के एनएच-320 डी (सोनुवा-चक्रधरपुर) पर रविवार को आसनातलिया के पास दो बाइकों की आमने- सामने हुई टक्कर में एक युवक की मौत हुई। इस दुर्घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोइलकेला के डालैकेला गांव के सत्यनारायण प्रधान और प्रवीण प्रधान चक्रधरपुर से सोनुवा की ओर बाइक से आ रहे थे। इस दौरान आसनातलिया के पास चक्रधरपुर की ओर जा रहे जामिद निवासी बाइक सवार राकेश लोहार, धनकृष्ण लोहार और अंश लोहार के साथ उनकी टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक पर सवार डालैकेला गांव के प्रवीण प्रधान की मौत हो गई। हादसे में चार लोग घायल हो गए। प्रवीण प्रधान को सिर और अन्य हिस्सों में गंभीर चोट लगी थी। उसे इलाज के लिए चक्रधरपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बाकी घायलों को सोनुवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर उपचार किया जा रहा है।

खुलासा डीआरएम ने पत्रकारों से कहा- हमारा पूरा फोकस ट्रेनों का सुरक्षित परिचालन

सिग्नल चोरी से थमी रफ्तार : चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेनें लेट

PHOTON NEWS CKP : दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेनों के लगातार लेट होने के पीछे अब चौकाने वाली सच्चाई सामने आई है। ट्रेनों की लेटलतीफी का लगातार विरोध हो रहा है। रविवार को चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम तरुण हरिया ने संवादादाता सम्मेलन कर खुलासा किया है कि सिग्नलिंग सिस्टम की लगातार हो रही चोरी ने ओर रेल परिचालन को संकट में डाल दिया है। चोरों के आतंक से न सिर्फ ट्रेनें लेट हो रही हैं, बल्कि रेल सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। बात दें कि पूरे रेल मंडल में यात्री ट्रेनें 10 घंटे तक लेट चलती हैं। इससे यात्री काफी परेशान हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेनों के प्रवेश करते ही ट्रेन लेट हो जाती है। डीआरएम ने ये बातें चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में रविवार को कहीं। उन्होंने



पत्रकारों को संबोधित करते डीआरएम तरुण हरिया

सिस्टम में चोरी की गई। अज्ञात चोर सिग्नलिंग गुमटी की दीवार तोड़कर अंदर घुस गए और कीमती तार व बैटरियां चुरा लीं। इस घटना के बाद पूरे सेक्शन में ट्रेन संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। उन्होंने बताया कि आदित्यपुर, गम्हरिया, बंडामुंडा, सीनी और डोंगुवापोशी जैसे इलाकों में लगभग हर सप्ताह सिग्नल चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। लगातार हो रही इस तरह की वारदातों से न केवल ट्रेनों की समय-सारिणी बिगड़ रही है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। हालांकि, ताजा मामले में आरपीएफ ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और जल्द खुलासा का भरोसा दिया है। प्रेस वार्ता में डीआरएम ने कहा कि हम लोडिंग के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम इस चक्र लोडिंग में

पीछे चल रहे हैं। हमारा पूरा फोकस ट्रेनों को समय पर और सुरक्षित चलाने पर है। इसी वजह से मंडल में कुछ समय के लिए विकास कार्यों पर भी ब्रेक लगाया गया है। उन्होंने यह भी माना कि हाथियों की आवाजाही और घना कोहरा ट्रेन संचालन के लिए अतिरिक्त चुनौती बने हुए हैं। हालांकि नई तकनीकों के जरिए इन समस्याओं से निपटने के प्रयास जारी हैं। पैसेंजर और मेट्रो ट्रेनों के रद होने के सवाल पर डीआरएम ने कहा कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जा रहा है और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में हरसंभव कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेनों की देरी की असली वजह अब सामने है। चोरों ने रेल सिस्टम की नसों पर ही वार कर दिया है।

बताया कि मंडल के कई स्टेशनों के आसपास सिग्नलिंग सिस्टम को बार-बार निशाना बनाया जा रहा है। इससे तकनीकी व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। चोरी की घटनाओं के कारण सिग्नल सिस्टम फेल होने की

स्थिति बन रही है, जो किसी बड़े रेल हादसे का कारण भी बन सकती है। डीआरएम ने ताजा घटना का जिक्र करते हुए बताया कि 9 जनवरी की देर रात करीब 1 बजे सीनी के पास ऑटो सिग्नलिंग

जेईई मेन : क्यूआर कोड से स्कैन होगा एडमिट कार्ड

JAMSHEDPUR : जेईई मेन- 2026 के लिए परीक्षा सेंटर की वेरिफिकेशन प्रक्रिया जारी है। इस बार परीक्षा केंद्र में अंगूठे का निशान नहीं लगाया जाएगा। क्यूआर कोड से छात्र का एडमिट कार्ड और पहचान पत्र स्कैन होगा। इसके साथ ही एनटीए भी सुरक्षा निर्देश तैयार कर रहा है। एग्जम के दौरान तीन स्तरों पर परीक्षार्थियों की जांच की जाएगी। सीसीटीवी से केंद्रीयकृत मॉनिटरिंग की जाएगी। इसकी निगरानी एआई से की जाएगी। जेईई मेन पेपर-1 का आयोजन 21 से 29 जनवरी तक किया जाएगा, जबकि पेपर-2 केवल 30 जनवरी को आयोजित की जाएगी। छात्रों को जूते, फुल स्लीव शर्ट, बड़े बटन वाले कपड़े और गहरे या तंग कपड़े पहनने की मनाही है। परीक्षा सुबह 9 से 12 और दोपहर 3 से 6 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। जमशेदपुर में इस परीक्षा के लिए एक केंद्र बनाया गया है, जहां करीब 7 हजार परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। **परीक्षा केंद्र पर प्रिंट कॉपी जरूरी :** एनटीए ने साफ किया है कि परीक्षा के दिन छात्रों को यह प्रमाणपत्र प्रिंट करके साथ लाना अनिवार्य होगा, ताकि केंद्र पर पहचान का फिजिकल वेरिफिकेशन हो सके। छात्रों को हालिया फोटो, हस्ताक्षरित और सत्यापित प्रमाण-पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। **आधार होना भी जरूरी :** जेईई मेन 2026 के अभ्यर्थियों के लिए एनटीए ने बताया कि कुछ छात्रों के आवेदन फॉर्म में अपलोड की गई लाइव फोटो और आधार, पहचान पत्र की फोटो में अंतर पाया गया है। ऐसे छात्रों को अब अपनी पहचान देवारा सत्यापित करने का अंतिम मौका दिया गया है। इसकी अंतिम तारीख 15 जनवरी है।

सोमा मुंडा के परिजनों से मिले चम्पाई सोरेन, बंधाया ढाढ़स

PHOTON NEWS KHUNTI : पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन रविवार को खूंटी पहुंचे, जहां वे दिवंगत पड़रहा राजा सोमा मुंडा के परिजनों से मिलकर शोक-संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने घटना की जानकारी ली और परिजनों को ढाढ़स बंधाया। यहां पत्रकारों से बातचीत में चम्पाई ने राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून-व्यवस्था की स्थिति बदतर हो चुकी है। सोमा मुंडा की हत्या के चार दिन बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होना प्रशासन की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने घोषणा की कि इस मुद्दे पर सामाजिक बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कदम उठाए



सोमा मुंडा की तस्वीर पर श्रद्धा-सुमन अर्पित करते चम्पाई सोरेन

जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनजातीय भूमि की लूट की मंशा से काम कर रही है। उन्होंने नगड़ी का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले भी जनजातीय जमीन पर कब्जे की कोशिश हुई थी, लेकिन आंदोलन के चलते ही जमीन बचाई जा सकी। उन्होंने कहा कि 'पेसा' के नाम पर जनजातीय समाज की पारंपरिक व्यवस्था को खतरे में डाला जा रहा है, जिससे उनकी परंपराएं समाप्त होने की आशंका है। इस मौके पर अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड प्रभारी लाल विजय नाथ शाहदेव ने कहा कि झारखंड में जल, जंगल और जमीन की बात करनेवालों की हत्या होना सरकार के लिए गंभीर सवाल है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंतनीय है।

कर्म से समाज परिवर्तन का समय : सरकार्यवाह दत्तात्रेय



समाज के लोगों को संबोधित करते आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले

JAMSHEDPUR : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का रविवार को जमशेदपुर में प्रवास हुआ। विभाग प्रचारक सत्यप्रकाश द्वारा सुव्यवस्थित योजना के अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गों के साथ दिनभर संगीष्ठियां आयोजित की गईं। विभाग प्रचार प्रमुख आलोक पाठक ने बताया कि होसबोले जी प्रांत प्रचारक गोपाल जी के साथ रांची से सड़क मार्ग द्वारा जमशेदपुर पहुंचे। बिष्टुपुर स्थित गुजराती सनातन समाज में तीन वर्गों में बैठकें हुईं। प्रथम बैठक में विभिन्न जातिक संगठनों के 375 से अधिक प्रतिनिधि, द्वितीय बैठक में 170 से अधिक संत-महात्मा तथा तृतीय बैठक में लगभग 210 आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि सहभागी बने। सामाजिक सद्भाव बैठक में जाति भेद, छुआछूत, धर्मांतरण, चुसपैठ, बांग्लादेश व नेपाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, नई शिक्षा नीति, युवाओं में बढ़ती नशाखोरी एवं सांस्कृतिक प्रदूषण जैसे विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। सरकार्यवाह ने कहा कि जैसे शरीर की मजबूती उसके अंगों से होती है, वैसे ही समाज की शक्ति प्रत्येक वर्ग के सकरात्मक आचरण और आपसी समन्वय से निर्मित होती है।

BRIEF NEWS

श्री राधा कृष्ण मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का समापन

RANCHI : राजधानी रांची के पुंदाग स्थित झारखंड के सबसे बड़े श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर में आयोजित तीन दिवसीय श्रीमद्भागवत कृष्ण कथा का समापन रविवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन प्रणामी ट्रस्ट के तत्वावधान में इसके संस्थापक स्वामी सदानंद जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित किया गया। इसमें रांची सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सहभागिता रही। कथा के अंतिम दिन कथावाचक सदानंद महाराज ने श्रीकृष्ण के अंतर्धान, राजा परीक्षित के मोक्ष सहित अनेक गूढ़ प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। अपनी वाणी और भजनों के माध्यम से उन्होंने भक्तों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।

एचईसी कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ेगी यूनियन : शनि

RANCHI : एचईसी श्रमिक संघ के अध्यक्ष शनि सिंह ने कहा कि एचईसी कर्मियों की सभी मांगों को कानूनी तरीके से दिलाने के लिए यूनियन लगातार प्रयास कर रही है। यूनियन की आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने रविवार को जारी प्रेस विज्ञापन में कहा कि वर्तमान में एचईसी की स्थिति ऐसी है कि अब कर्मचारियों की उम्मीदें सरकार से ही जुड़ी हुई हैं।

झारखंड के कराटे खिलाड़ियों ने जीते सात मेडल



RANCHI : कोलकाता में जेटेकन शितोरियू कराटे टू एप्सोसिएशन इंडिया के तत्वावधान में आयोजित बोंगो भूमि कप अंतरराष्ट्रीय कराटे चैम्पियनशिप में झारखंड के कराटे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। राज्य के खिलाड़ियों ने तीन स्वर्ण सहित कुल सात पदक जीतकर देश का परचम लहराया। काता स्पर्धा में आदित राज ने नेपाल के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और देश का खाता खोला। इसके बाद एरोन शीतल खलखो ने काता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साक्षी ओझा ने कैटेड कुमिते में स्वर्ण और काता में रजत पदक जीते। मिस्ट्री कुमारी ने काता में रजत और कुमिते में कांस्य पदक, जबकि मोहम्मद हुजयफा अनवर ने काता में कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन कराटे इंडिया के रेफरी कमीशन चेरमैन हांशी प्रेमजीत सेन और ट्राइबल एवं माइनिस्ट्री डेवलपमेंट कमीशन चेरमैन रेंसी सुनील किस्पोट्ट ने दी प्रशंसा कर किया। सफल खिलाड़ियों को इमा के अध्यक्ष अनिल किस्पोट्ट और अन्य गणमान्य ने बधाई दी।

चेशायर होम पहुंचे सीएम हेमंत व कल्पना, दिव्यांग बच्चों से की मुलाकात

PHOTON NEWS RANCHI : रविवार को शिवू सोरेन की जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बरियातू स्थित चेशायर होम पहुंचे। वहां के दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारे जीवन का पहला अवसर है, जब हम बाबा दिशोम गुरु शिवू सोरेन की जयंती उनके बिना मना रहे हैं। गुरुजी के संघर्ष, त्याग और बलिदान ने हमें अलग राज्य के सपने को साकार करने की राह दिखाई। वे सदैव कमजोर, पिछड़े और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए समर्पित रहे। गुरुजी के विचार और आदर्श सदियों तक हम सभी का पथप्रदर्शन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री और कल्पना

■ सीएम ने हरसंभव सहयोग का दिया भरोसा बोले- दिव्यांग बच्चों की शक्ति किसी से कम नहीं



सोरेन ने बच्चों के साथ कुछ समय बिताया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बच्चों में कंबल व आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चेशायर होम से उनका एक विशेष भावनात्मक जुड़ाव रहा है। वे अक्सर यहां आते रहे हैं और समय-समय पर वहां के सदस्यों और बच्चों से मिलते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने यहां की व्यवस्था और देखरेख की सराहना करते हुए कहा कि यहां के

बच्चों के उज्वल भविष्य की कामना

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संस्था को हरसंभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया तथा उपस्थित सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने बच्चों के उज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजन कल्याण के क्षेत्र में निरंतर रूप से सार्थक प्रयास कर रही है। कार्यक्रम के दौरान विधायक कल्पना सोरेन ने भी बच्चों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही संस्था में संचालित सेवा कार्यों की सराहना की।



महसूस होता है कि उनकी शक्ति और आत्मविश्वास किसी भी प्रकार से कम नहीं है। बच्चों की प्रतिभा देखकर यह सदस्य त्याग और समर्पण की भावना से कार्य कर रहे हैं। यहां के दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा देखकर यह

भाई-बहन को खोज पाने में अब तक रांची पुलिस विफल, बढ़ रहा जनाक्रोश

बच्चों के गायब होने के विरोध में धुर्वा बंद का दिखा व्यापक असर

PHOTON NEWS RANCHI : मासूम भाई-बहन को खोज पाने में रांची पुलिस अब तक विफल है। इसके खिलाफ अब जनाक्रोश सामने आने लगा है। रविवार को दोनों बच्चों के रहस्यमय रूप से गायब होने के विरोध में स्थानीय लोगों ने धुर्वा बंद रखा। इसका व्यापक असर देखने को मिला। दरअसल, दो मासूम भाई-बहन अंश और अंशिका के रहस्यमय परिस्थितियों में गायब होने और पुलिस द्वारा नौ दिन बीत जाने के बाद भी दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलने से अब जनता के सब्र का बांध टूटने लगा है। इसे लेकर जगह-जगह आंदोलन हो रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को धुर्वा बंद का एलान भी पूर्णतः सफल नजर आया।

■ मेडिकल स्टोर छोड़कर बंद रही सभी दुकानें लोगों ने पुलिस पर उठाए सवाल



सीआईडी ने पूरे देश की पुलिस से मांगी मदद

मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सीआईडी ने अब इस मामले को लेकर पूरे देश की पुलिस से मदद मांगी है। सीआईडी, रांची के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मनोज कोशिक देशभर के डीजीपी, पुलिस आयुक्त और आईजी को हू एंड फाई पुलिस द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना है, जिसमें किसी वंशित अपराधी या गमगुंथूदा व्यक्ति के बारे में जानकारी मांगी जाती है, ताकि जनता की मदद से उसे पकड़ा जा सके। नोटिस भेजा है। पत्र में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के थानों, आउट पोस्ट और बीट हाउसों में दोनों बच्चों की जानकारी प्रसारित कर पृच्छाछ कराने को कहा गया है। पत्र में यह भी बताया गया है कि यह मामला धुर्वा (रांची) थाना क्षेत्र का है, यहां धुर्वा थाना कांड संख्या 01/2026 दिनांक 03/01/2026 दर्ज की गई है। केस, भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत दर्ज हुआ है और जांच की निगरानी सीआईडी कर रही है। किसी भी व्यक्ति को यदि बच्चों के बारे में जानकारी, उनकी मौजूदगी या सदिध गतिविधि का पता चलता है तो वह सीआईडी झारखंड, रांची को सूचना दे सकता है। सूचना के लिए ईमेल और मोबाइल नंबर 9771432139 जारी किया गया है।

में घोर लापरवाही बरती है। लोगों का मानना है कि दो जनवरी को बच्चे गायब हुए थे, लेकिन पुलिस चार जनवरी को पकड़ आई। गायब बच्चों को लेकर केवल धुर्वा ही नहीं बल्कि पूरा रांची शहर एकजुट हो चुका है। यही वजह है कि धुर्वा स्थित लगभग 200 से ज्यादा दुकानें बंद हैं।

कैलाश यादव ने बताया कि आम लोग सदमे में हैं और उनमें भारी आक्रोश है। पुलिस केवल आश्वासन दे रही है। बच्चे कहा है? इसका उन्हें अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं धुर्वा के स्थानीय लोगों ने खुद ही बंद का समर्थन किया है। सूचना देने पर 51 हजार रुपये का पुरस्कार : बता दें कि दो जनवरी के दिन रहस्यमय तरीके से भाई-बहन अंश (5 वर्ष) और अंशिका (4 वर्ष) गायब हो गए थे। उन्होंने दूढ़ने के लिए रांची पुलिस का पूरा महकमा लगा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके नौ दिन बीत जाने के बाद भी दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला है। रांची पुलिस ने बच्चों को खोज निकालने के लिए इनाम की राशि की भी घोषणा कर दी है। बच्चों का पता बताने वाले को 51 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही बच्चों की फोटो और पुरस्कार राशि के साथ रांची के विभिन्न इलाकों में पोस्टर चस्पा किए गए हैं।

अभी शीतलहर से राहत नहीं, 13 जिलों के लिए 15 तक येलो अलर्ट

PHOTON NEWS RANCHI : फिलहाल झारखंड में सीट लहर से राहत की उम्मीद नहीं है। कहीं-कहीं पहले की अपेक्षा किसका असर बढ़ गया है। रविवार को मौसम विभाग ने 13 से 15 जनवरी के बीच राज्य के 13 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, शीतलहर का प्रभाव मुख्य रूप से राज्य के उत्तर-पश्चिमी और उससे सटे जिलों में देखने को मिलेगा। अलर्ट के मुताबिक 13 और 14 जनवरी को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग और गुमला जिलों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है। 15 जनवरी को गढ़वा, पलामू, गुमला, लातेहार, चतरा और लोहरदगा में टंड और बढ़ने की संभावना है। इधर, राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में रविवार की सुबह मौसम साफ रहा, लेकिन दिनभर मध्यम दर्जे की ठंडी हवाएं चलती रहीं। ठंडी हवाओं के कारण लोगों को दिन में भी कनकनी महसूस होती रही। सुबह और शाम के समय ठंड का असर ज्यादा होगा। रांची में रविवार को अधिकतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।



■ गुमला में दर्ज किया गया 2.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान

जमशेदपुर में अधिकतम 25.6 और न्यूनतम 11.4 डिग्री, डाल्टेनगंज में 26.2 और 4.9 डिग्री, बोकारो में 22.5 और 7.1 डिग्री तथा चाईबासा में अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को शीतलहर को देखते हुए सावधानी बरतने, सुबह-शाम आवश्यक रूप से बाहर न निकलने और टंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है। हजारीबाग, खुंटी और लोहरदगा में भी अधिक ठंड देवघर में 24.7 और 7.9 डिग्री, कोडरमा में 22.9 और 8.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। गुमला में राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री दर्ज किया गया।

अवैध हथियारों की डील से पहले पुलिस के हथे चढ़े 5 तस्कर, बड़ी संख्या में हथियार बरामद

PHOTON NEWS RANCHI : रांची पुलिस ने अवैध हथियार खरीद-बिक्री के एक बड़े नेटवर्क को खूलासा करते हुए पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हिंसापीढ़ी थाना क्षेत्र की बड़ी मस्जिद लेन रोड में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को सूचना मिली थी कि देर रात इलाके में अवैध हथियारों की डील होने वाली है। इसके बाद सिटी एसपी के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली और सदर के नेतृत्व में एक छापामारी दल गठित की गई। रात करीब 11:20 बजे जब पुलिस टीम बड़ी मस्जिद के पास पहुंची, तो एक सदिध भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़



बिहार से लाकर करते थे सप्लाई

पुछाछ में मो. कबीर ने खुलासा किया कि वह अपने सहयोगियों के साथ बिहार के कैमूर और मुंगेर से हथियार लाकर रांची में अपराधियों को सप्लाई करता है। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर शाहनवाज आलम, मो. सैफ उर्फ शेर, अनुज टाकुर और अकिंत कुमार को गिरफ्तार किया। इनके पास से फैक्ट्री मेड पिस्टल, तीन देशी कट्टा, एक छह चक्रिय देशी रिवाल्वर और कुल 110 जिंदा गोलियां बरामद की गईं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है और सभी के खिलाफ सबूतित थानों में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम मो. कबीर उर्फ बबलू उर्फ बोना बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक 9 एएमएम पिस्टल, दो मैगजीन और 20 गोलियां बरामद की गईं। वैध कागजात नहीं दिखा पाने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

टुसू पर्व झारखंड की पहचान का प्रतीक : देवेंद्रनाथ महतो

RANCHI : झारखंडी भाषा, खतियान संस्कृति समिति की ओर से रविवार को राजधानी रांची के मेन रोड क्षेत्र में आयोजित राजधानी टुसू महोत्सव पारंपरिक उत्साह, लोक आस्था और सांस्कृतिक रंगों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान मंच पर कलाकारों ने नाटिका, लोकगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महोत्सव के मुख्य अतिथि देवेंद्रनाथ महतो ने अपने संबोधन में कहा कि टुसू पर्व केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि झारखंड की सामाजिक एकता, लोक संस्कृति और सामूहिक आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, परंपराओं और लोक विरासत से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।

झारखंड के आयुष्मान आरोग्य लोकेटर को मिला स्कॉच अवार्ड, की गई सराहना

PHOTON NEWS RANCHI : डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य की नागरिक केंद्रित पहल आयुष्मान आरोग्य लोकेटर को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 11 जनवरी को दिल्ली स्थित इंडिया रेंटिटेज सेंटर में आयोजित सम्मान समारोह में प्रदान किया गया। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की इस पहल के लिए मिशन डायरेक्टर-सह-अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंजक और उनकी टीम को यह सम्मान मिला है। स्कॉच के चेयरमैन समीर कोचर ने ये अवार्ड दिया।



गुगल सर्च के जरिए आसपास की स्वास्थ्य सुविधाओं की मिल रही जानकारी

स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण उपलब्ध
इस लेटेफॉर्म पर अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की फोटो, दिशा-निर्देश, संपर्क नंबर और उपलब्ध सेवाओं का विवरण उपलब्ध है। खास बात यह है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर तक मीपिंग पूरी की गई है, ताकि ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी आसानी से पहुंच रही है। यह पहल पारदर्शिता बढ़ाने, सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने और समय पर उपचार सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध हो रही है।

आयुष्मान आरोग्य लोकेटर आम लोगों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से लोग केवल एक गुगल सर्च के जरिए अपने आसपास की स्वास्थ्य सुविधाओं की सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

युवा दिवस

राजधानी में सड़कों को कराया गया अतिक्रमण मुक्त

नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने का चलाया विशेष अभियान

PHOTON NEWS RANCHI : सोमवार को स्वामी विवेकानंद जयंती (युवा दिवस) मनाया जाएगा। इसे लेकर रांची नगर निगम ने शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया। अभियान में विशेष रूप से बड़ा तालाब (विवेकानंद सरोवर) और छोटा तालाब क्षेत्र में सफाई के साथ अतिक्रमण मुक्त अभियान भी चलाया गया। नगर निगम की एन्फोर्समेंट टीम ने कई अवैध टेले, खोमचे, अस्थायी दुकानें और मालवाहक वाहन हटाए। जिससे सड़कें साफ और जाम-मुक्त हो गईं। छोटा तालाब क्षेत्र में भी अस्थायी संरचनाओं को हटाकर लोगों के लिए सुरक्षित

तालाबों के किनारे और आसपास के सार्वजनिक स्थलों की हुई सफाई



मार्ग सुनिश्चित किया गया। इस कार्रवाई के दौरान दुकानदारों और लोगों को चेतानवी दी गई कि भविष्य में सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण न करें। स्वच्छता अभियान के तहत तालाबों के तटीय क्षेत्रों और आसपास के सार्वजनिक स्थलों की सफाई की गई। नालियों को रूत में आने जाने में परेशानी नहीं होगी। सहजानंद चौक में भी चला अभियान : रांची नगर निगम की को ध्यान में रखते हुए तालाब क्षेत्र में खराब स्ट्रीट लाइट को रूत में आने जाने में परेशानी नहीं होगी। सहजानंद चौक में भी चला अभियान : रांची नगर निगम की

इंफोर्समेंट टीम द्वारा वार्ड संख्या-26 अंतर्गत सहजानंद चौक पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। शहर के प्रमुख चौकों में से एक सहजानंद चौक के सभी मार्गों को लेफ्ट-प्री और अतिक्रमण मुक्त रखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से उक्त अभियान संचालित किया गया। इस दौरान 8 अस्थायी संरचनाओं को हटाया गया, जिसमें 1 टेला एवं 2 गुमटियों के अलावा अतिक्रमण सामग्रियों को जन्म दिया गया। अतिक्रमणकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में पुनः उक्त स्थल पर दुकान अथवा अस्थायी संरचना स्थापित न करने हेतु सख्त निर्देश दिया गया।

राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता में अनुष्का ने जीता कांस्य पदक

RANCHI : झारखंड की उभरती खिलाड़ी अनुष्का कुमारी ने 69वीं राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य को कांस्य पदक दिलाया है। उन्होंने यह उपलब्धि अंतर-14 बालिका वर्ग के 38 किलोग्राम से अधिक भारवर्ग में हासिल की। झारखंड की ताइक्वांडो टीम स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची की अगुवाई में इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल हुई थी। यह प्रतियोगिता पंजाब के लुधियाना स्थित जीएसएसएसएस हॉल में 6 जनवरी से 11 जनवरी तक आयोजित की गई। अनुष्का कुमारी ने अपने पहले मुकाबले में तमिलनाडु की खिलाड़ी को 2-0 से पराजित कर शानदार शुरुआत की।

चान्हे में हाथियों ने मचाया उत्पात फसलों को पहुंचाया नुकसान

PHOTON NEWS RANCHI : चान्हे प्रखंड की भूतो पंचायत अंतर्गत कुल्लू गांव में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। देर रात पहाड़ी इलाकों से उतरकर आए हाथियों के झुंड ने गांव में घुसकर भारी उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और खेतों में लगी फसलों को भी रौंद दिया। हाथियों के आनाक नाव पहुंचने से इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों के अनुसार, हाथियों के झुंड ने कुल्लू गांव में सात घरों में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं करीब 40 बोरा घर में रखा धान हाथियों ने खा लिया, जिससे पीड़ित परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इससे पहले भी भूतो पंचायत और आसपास के कई गांवों में हाथियों द्वारा नुकसान पहुंचा जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। विधायक प्रतिनिधि मारवाडी उरांव, अबुल्लाह अंसारी और किशोर भगत ने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क कर हाथियों से बचाव की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से उअर तक हाथियों को भगाने या स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

पेज 01 का शेप
क्राइम हॉटस्पॉट : 10 महीनों में 115 मर्डर...
अक्टूबर में चोरी के मामलों ने 10 महीनों का तोड़ा रिकॉर्ड : सितंबर में हत्या के 12, दुर्घर्म के 16, लूट के 3 और गृहभेदन के 27 मामले सामने आए, जबकि चोरी की 184 और दंगा की 3 घटनाएं दर्ज की गईं। इसी महीने शास्त्र अधिनियम के 6 और विविध क्राइम के 4 मामले सामने आए। अक्टूबर में चोरी के मामलों ने 10 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 210 का आंकड़ा छू लिया, वहीं हत्या के 10 मामले सामने आए। इसी महीने अपहरण के 14, दुर्घर्म के 16, लूट के 2 और गृहभेदन की 35 घटनाएं और दंगा का 1 मामला सामने आया। शास्त्र अधिनियम के 12, नक्सल गतिविधियों का एक और विविध क्राइम के 464 मामले सामने आए।

शहरनामा



वीरेंद्र भोज्रा

मेयर-मयूरी

तीसरे स्तर की लोकशाही का चुनाव होने वाला है। इसका विगुल बजने के साथ ही यह भी तय हो गया कि कोल्हान की तथाकथित राजधानी मानगो, आधी आबादी के लिए आरक्षित रहेगी। इसका कयास तो पिछले बार से ही लगाया जा रहा था, जब मयूरी के चुनाव लड़ने में तकनीकी पंच आते ही पूरे सूबे का निकाय चुनाव स्थगित हो गया था। बहरहाल, पिछले बार वाली कैडिडेट यानी मयूरी तो तय हो गई है, बच्चों के फेर में फंसे अप्रत्याशित उम्मीदवार ने भी मयूरी के पक्ष में राय सुना दी है। तान्जुब तो तब होता था, जब अलग-अलग श्रेणी में उस कब्र को भी सफाई का सरताज बताया जाता था, जो साल भर गंदगी से जंग करता रहता है। जनप्रतिनिधि भी नाक बंद करके गलियों से गुजरते थे, लेकिन पुरस्कृत मिलने पर बधाई देते नहीं थकते थे। अब पता चला कि सर्वे के दौरान लोगों के मोबाइल छिनकर कैसे रेंटिंग दिलाई जाती थी।



कान बंद कर लिए। इसके साथ ही उन शहरवासियों की आंखें भी खुल गईं, जो हर बार सफाई का ढोंग रचकर चैंपियन बनने की होड़ में लग जाते थे। अपनी लौहगरी भी अडूती नहीं है। ऊपर-ऊपर साफ दिखने या दिखाने के चक्कर में कितनी गंदगी कहां डंप हो जाती थी, इसकी पोल भी कई बार खुल चुकी है। तान्जुब तो तब होता था, जब अलग-अलग श्रेणी में उस कब्र को भी सफाई का सरताज बताया जाता था, जो साल भर गंदगी से जंग करता रहता है। जनप्रतिनिधि भी नाक बंद करके गलियों से गुजरते थे, लेकिन पुरस्कृत मिलने पर बधाई देते नहीं थकते थे। अब पता चला कि सर्वे के दौरान लोगों के मोबाइल छिनकर कैसे रेंटिंग दिलाई जाती थी।

कंबल ही कंबल

मैं यहां किसी सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, ना किसी का प्रचार कर रहा हूँ। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, जो टंड के मौसम का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें गरीबों को कंबल देकर

जितनी खुशी नहीं मिलती है, उतनी अखबार-चैनल में अपनी फोटो-वीडियो देखकर मुस्कान खिल जाती है। हालांकि, इसी शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो सौ-पचास कंबल बांट देते हैं और किसी को कानों-कान खबर तक नहीं लगती। इसमें एक असामान्य बात यह देखने में आती है कि गरीबों का इलाका लगभग फिक्स रहता है। एक ही गांव-मोहल्ले में हर सीजन में 8-10 लोग कंबल बांट आते हैं। इस हिसाब से उनके यहां कंबलों का गोदाम बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वे हर बार टंड में उसी चौथड़े में नजर आते हैं। शायद ही किसी कंबल बांटने वाले ने इस बात पर कभी चिंतन किया होगा।

गोलचक्कर पर एक्सीडेंट

साकची में पड़ने वाले बस स्टैंड के गोलचक्कर पर दो दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बाइक सवार दंपती कुचल दिए गए। विडंबना यह है कि वहां कम से कम आधा दर्जन खाकी-सफेद वदीधारी भारी वाहनों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए बैचन दिखाई देते हैं। हर पांच मिनट पर पुल को जाम होते हुए देखा इनके मन को सुकून देता है। बहरहाल, इतने वदीधारियों की मौजूदगी में जिस वाहन की स्पीड 10 किलोमीटर होनी चाहिए, वह दस गुणा बढ़ गई। एनएच की तरह वह वाहन बाइक सवार दंपती को रौंदते हुए घसीट ले गया। इससे भी आश्चर्य की बात यह रही कि वह सभी वदी वालों की आंख में धूल झाँकते हुए फरार भी हो गया। बाद में भी उसे सख्त सजा नहीं मिलने वाली है, यह भी तय है। जब उसे यहां के आला अधिकारियों ने ही वीआईपी बनाकर रखा है, तो कार्रवाई कौन करेगा।

सड़क दुर्घटना में युवक की मौत पर टीएमएच में हंगामा



अस्पताल परिस्तर में परिजनों को समझाते पुलिस पदाधिकारी व इनडेंट में मृतक

JAMSHEDPUR : बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को देर रात हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। बिष्टुपुर स्थित के. रोड निवासी राजकुमार नाग (40) को टीएमएच में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसे लेकर परिजनों ने रविवार को टीएमएच में हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि राजकुमार को धक्का मारने वाले कार के चालक को पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। अब तक दोषी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। परिजन मृतक के आश्रित को मुआवजा देने और आरोपी पर तत्काल कार्रवाई की मांग पर अड़े थे। प्रदर्शन के दौरान टीएमएच परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थिति को संभालने के लिए काफी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे। परिवार के लोगों ने बताया कि राजकुमार घर में कमाने वाला इकलौता सदस्य था। ड्यूटी से लौटते समय सड़क पर करने के दौरान वह हादसे का शिकार हो गया। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मानगो गोलचक्कर पर घायल महिला ने भी तोड़ा दम, थाने पर किया प्रदर्शन

JAMSHEDPUR : मानगो बस स्टैंड के पास सड़क दुर्घटना ने एक परिवार को ही उजाड़ कर रख दिया। शनिवार को शाम करीब चार बजे हुए हादसे में पति की मौत पर ही मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी ने रविवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पति-पत्नी दोनों की असमय मौत से उनके दो बच्चे अनाथ हो गए। इससे स्थानीय लोगों में शोक और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों के अनुसार, मानगो के डिमना रोड स्थित विश्वकर्मा लाइन निवासी लाल शर्मा शनिवार को बस स्टैंड के सामने गोलचक्कर पर एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गए थे। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि लाल शर्मा की मौत पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी नीतू शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत लगातार नाजुक बनी रही। मौत की खबर मिलते ही घटनास्थल और अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई। घटना से आक्रोशित स्थानीय व विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग रविवार को सीतारामदेरा थाना पहुंचे। उन्होंने वहां प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ सारबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मानगो बस स्टैंड क्षेत्र में स्थायी और प्रभावी ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जाए। इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और हादसों पर अंकुश लगाने के लिए टोस कदम उठाए जाएं। लोगों ने मृतक दंपती के दोनों बच्चों को तत्काल मुआवजा, सरकारी सहायता और संरक्षण देने की भी मांग की।



सीतारामदेरा थाना में हंगामा कर रहे लोग, लाला कुमार व नीलम शर्मा की फाइल फोटो

समाचार सार

ध्वस्त की गई 3 शराब भट्टियां, एक टन महुआ जवत

CHAIBASA : पश्चिमी जिला में उत्पाद विभाग ने झोंकपानी थाना क्षेत्र के गुडगांव में छापेमारी की, जिसमें 3 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। यहां 1000 जावा महुआ और 70 लीटर अवैध देसी शराब जवत किया गया। छापेमारी के दौरान भट्टी संचालक फरार हो गया। उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि कार्रवाई के दौरान शराब के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को भी जवत किया गया है। मामला दर्ज कर फरार संचालक को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है।

जरूरतमंदों में बांटे गए कंबल व इस्टबिन

JAMSHEDPUR : मानगो स्थित गुरुद्वारा रोड में श्रीश्री विश्वनाथ मंदिर (शिव मंदिर) के प्रांगण में विधायक सरजू राय के सौजन्य से श्रीश्री विश्वनाथ सेवा समिति के बैनर तले जनसुविधा प्रतिनिधि- उच्च शिक्षा, पवन सिंह के नेतृत्व में कंबल व इस्टबिन

वितरण किया गया। पवन सिंह ने बताया कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए और बस्ती में गंदगी न फैले इसी सोच के साथ 200 जरूरतमंद महिला-पुरुषों के बीच कंबल व इस्टबिन बांटे गए। सभी ने कहा कि वार्ड संख्या-35 में ऐसा नेता चाहिए, जो हर किसी के सुख-दुख में जो नेता 24 घंटा खड़ा रहे। सड़क, नाली, लाइट सभी की समस्या में जो नेता हर कदम आमो रहता है, लोगों ने उसी को समर्थन देने का मन बना लिया है।

वीमेंस यूनिवर्सिटी के शिक्षकेतर कर्मियों ने मनाई खुशियां

JAMSHEDPUR : जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मियों ने रविवार को पहाड़भागा में पिकनिक मनाकर एक-दूसरे के साथ खुशियां साझा कीं। कर्मचारी संघ, के उपाध्यक्ष चैतन्य शिरोमणी के नेतृत्व में हुआ आयोजन पूर्णतः मनोरंजक, सौहार्दपूर्ण व परस्पर समन्वय से संपन्न हुआ। इसमें विश्वविद्यालय के परमानेंट, वोकेशनल, आउटसोर्सिंग एजेंसी तथा सेवानिवृत्त कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में जन्यकिशोर प्रसाद, तपन पात्रा, भीमसेन पूरण एवं चैतन्य शिरोमणी ने अग्रणी भूमिका निभाई।

मना ठाकुर अनुकूलचंद्र का आविर्भाव दिवस

JAMSHEDPUR : एफ्रिको क्लब हाउस में रविवार को श्रीश्री ठाकुर अनुकूलचंद्र का 1388वां आविर्भाव दिवस धूमधाम से मनाया गया। जमशेदपुर सत्संग समिति द्वारा आयोजित दो दिवसीय उत्सव सुबह 10.30 बजे 'बंदे उद्योगतः- उच्चारण के साथ प्रारंभ हुआ। इसमें डॉ. सुखेंद्र पाणि ने कोलकाता से आए विशेष वक्ता प्रलय मजुमदार और सम्पद नारायण बनर्जी का ठाकुर अनुकूलचंद्र पर आधारित साक्षात्कार लिया। विशिष्ट अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी लोगों को संबोधित किया।

पिकनिक मना रहे लोगों पर चढ़ी कार, लोगों ने वाहन में लगा दी आग

PHOTON NEWS GHATSILA :

पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला थाना क्षेत्र स्थित बुरुडीह डैम में रविवार को पिकनिक मना रहे लोगों पर एक कार चढ़ गई। शाम लगभग 4 बजे जमशेदपुर के सोनारी और डिमना से आए परिवार के लोग खाना खा रहे थे, उसी दौरान बंगाल के गोपीबल्लवपुर से आई बोलैरो कार उन पर चढ़ गई, जिससे लगभग 10 लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी ओर घटना से आक्रोशित लोगों ने घटना स्थल पर ही कार में आग लगा दी, जिससे कार जलकर खाक हो गई। सभी घायलों को स्थानीय लोग एवं पुलिस की मदद से इलाज के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना में कृष्णा पाल



अनुमंडल अस्पताल पहुंचे लोग व धू-धूकर जलती कार

का पैर टूट गया है, जिसे घाटशिला अनुमंडल अस्पताल से एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया है, वहीं अन्य घायलों में वरुण विश्वकर्मा, संतोष महतो, मनीष महतो शामिल हैं, उनका प्राथमिक उपचार घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में किया जा रहा है। अन्य घायलों को मामूली चोट लगी है। दूसरी ओर इस घटना में बोलैरो कार का चालक भी



फोटोन न्यूज

घायल हो गया। उसे पुलिस की निगरानी में घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार, सोनारी और डिमना से तीन ऑटो पर सवार होकर लोग बुरुडीह डैम में पिकनिक मनाए आए थे। वे लोग तिरपाल बिछाकर खाना खा रहे थे, कुछ लोग आराम कर रहे थे। इसी दौरान कार के चालक सनातन

मनरेगा को पुनः बहाल करने के लिए कांग्रेस ने दिया धरना



साकची में धरना देते कांग्रेस कार्यकर्ता

JAMSHEDPUR : अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमिटी के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत रविवार को जिलाध्यक्ष परचंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साकची में पुराना कोर्ट के समीप डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला पर्यवेक्षक बलजीत सिंह बेदी उपस्थित थे। धरना एवं उपवास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बलजीत सिंह बेदी व परचंदर सिंह ने कहा कि मोदी सरकार दुर्भाग्यपूर्ण उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय गांरटो रोजगार अधिनियम (मनरेगा) को छिन्न-भिन्न करते हुए मूल स्वरूप को बदलकर मजदूरों के रोजगार को ही समाप्त करने पर तुल गई है। कांग्रेस सरकार में 90% राशि केंद्र सरकार उपलब्ध कराती थी, लेकिन मोदी सरकार ने केंद्र का हिस्सा 60% करके राज्य सरकार को 40% राशि के चक्कर में डाल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ठाना है कि मजदूरों के हकों के हर हाल में दिलाने के लिए मनरेगा को मूल रूप में वापस लाने के लिए कटिबद्ध है।

डॉ. अशोक अतिविल ने की राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता

JAMSHEDPUR : करनडीह

स्थित एलबीएसएम कॉलेज के प्राचार्य और हिंदी व मैथिली के जाने-माने साहित्यकार डॉ. अशोक अतिविल ने पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता की। उन्होंने उद्घाटन सत्र के अतिथि एवं राजकमल पर केंद्रित सत्र के अध्यक्ष के रूप में प्रभावी हस्तक्षेप किया। छायावाद की सशक्त हस्ताक्षर महादेवी वर्मा एवं अकविता आंदोलन के प्रतिष्ठित पाठकों में से एक राजकमल की आवृत्ति एवं विमर्श पर आधारित इस संगोष्ठी में देश भर के विद्वान शामिल थे। इसमें 15 शोध आलेखों की भी प्रस्तुति हुई, जबकि 25 युवक-युवतियों ने आवृत्ति पाठ किया। डॉ. अतिविल ने अकविता आंदोलन के परिवेश, प्रभाव एवं राजकमल के योगदान पर कहा कि मैथिली हो या हिंदी साहित्य, राजकमल दोनों साहित्य के रचनाधर्मिता को आलौडित करते हैं। आप उनसे असहमत हो सकते हैं, पर उनके साहित्य की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।

22 लोगों की जान लेने वाला दंतैल हाथी अब घरों पर कर रहा हमला

PHOTON NEWS CHAIBASA :

पश्चिमी सिंहभूम जिले में 22 लोगों की जान लेने वाला दंतैल हाथी अब भी पकड़ से बाहर है। अब वह घरों और फसलों को नष्ट कर रहा है। ताजा मामला मड़गांव थाना क्षेत्र के शियालजोड़ा गांव से आया है, जहां लोग दंतैल हाथी के कहर से परेशान हैं। पूरी रात जाग कर ग्रामीण अपनी और अपने परिवार को रखवाली कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हाथी शनिवार को रात करीब 10.30 बजे शियालजोड़ा गांव में घुस आया और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। हाथी ने जयनाथ महतो और ईश्वर महतो के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया और घर में रखा अनाज जरूरी के घर के पास लगे सक्जी के खेत को तहस-नहस कर दिया।



हाथी को पकड़ने के लिए मौजूद वन विभाग की टैपेक् टीम

इसके बाद ग्रामीणों ने एकजुट होकर मशालें जलाई और फटाखे फोड़े, तब कहीं जाकर घंटों बाद हाथी गांव छोड़कर जंगल की ओर चला गया। घटना के बाद गांव में दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और हाथी के स्थायी समाधान की मांग की है। आसपास के गांव में भी करीब 20 ग्रामीण एक सुरक्षित घर में एक साथ रात बिता रहे हैं। इस घर में अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं, जबकि पुरुष रातभर बाहर रहकर

फंदे पर लटककर पेंटर ने दी जान

तनाव की आशंका

JAMSHEDPUR : कदमा के भाटिया बस्ती में एक पेंटर ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम संजय कुमार (43) है। रविवार सुबह जब परिजन उसे जगाने उसके कमरे में पहुंचे तो वह फंदे पर लटका मिला। घटना की पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमॉर्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया गया। संजय कुमार पेशे से पेंटर था और मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। घटना के वक्त उसकी पत्नी मायके गई थी। परिजनों के मुताबिक पति-पत्नी के बीच घरलू बातों को लेकर अक्सर नोकझोंक होती रहती थी। साल 2011 में दोनों की शादी हुई थी और उनके एक छोटा बच्चा भी है। लोगों का कहना है कि संजय मिलनसार व्यक्ति था। लेकिन, पिछले कुछ समय से परिवारिक तनाव के चलते वह मानसिक रूप से परेशान था। हालांकि खुदकुशी के पीछे का सच कारण अब तक सामने नहीं आ सका है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और परिजनों सहित आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

आयोजन पूर्वी सिंहभूम साहित्य उत्सव में सबसे पहले जयंती पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि

बोली-भाषा पर साहित्यकारों ने किया मंथन, छऊ नृत्य ने खूब बटोरी तलियां

PHOTON NEWS JSR :

प्रथम पूर्वी सिंहभूम साहित्य उत्सव का रविवार को समापन हो गया। इसमें सत्रों की शुरुआत से पहले दिशोम गुरु शिबू सोरेन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी सहित सभी साहित्यकार उपस्थित थे। तृतीय दिवस के प्रथम सत्र में आयोजित उपाध्यक्ष से यदुवंश प्रणय की -टू लैंग्वेजस वन इनर वर्ल्ड- विषय के बहाने अनुकृति के जीवन संदर्भों और रचना प्रक्रिया पर गर्मजोशी से की गई बातचीत से सभागार का माहौल ऊर्जा से भर गया। इसी क्रम में वैश्विक साहित्य को जन सुलभ बनाने के लिए अनुवादकों की भूमिका पर अनुकृति ने कहा कि भाषा को साधा जाना चाहिए, देश, काल और समय के दायरे में बांधा

नहीं जाना चाहिए और यह काम अनुवादक कर रहे हैं। कहानियों की भाषा परिवेश और काल भिन्न हो सकते हैं, परंतु मानवीय सरोकार सावदेशिक और सर्वकालिक है। जीवन में स्मृतियां और उम्मीद की प्रासंगिकता को बर्ण करते हुए वह जापानी किंतुगो कला का उदाहरण जीवन प्रसंगों से जोड़ते हुए बताया कि कि टूटी उम्मीद, टूटी आशाएं, टूटा पात्र बेकार है। यह सोच हमारी दृष्टि का दोष है इसे अच्छे भावों, समझ और अध्ययन से मढ़कर हम जीवन को पहले से ज्यादा अर्थवान और खूबसूरत बना सकते हैं। रचना प्रक्रिया पर बात करते हुए वह रोमन भाषा में रचित अपने उपन्यासों भंवरु और दौरा के पात्र संदर्भ में युभुत्त जनजाति गाड़िया लोहार की बात करती हैं। वह बताती है पितृसत्तात्मक



यदुवंश प्रणय से संवाद करती अनुकृति उपाध्यक्ष

जनजाति होते हुए वहां स्त्रियां अपनी बुनियादी कला के दर्प से अपनी सौंदर्य चेतना, स्वातंत्र्य और वजूद को कल्पनाओं के पहले से भरा रखती हैं, क्योंकि कल्पनायें खत्म हो जाएगी तो स्मृतियां खत्म हो जाएगी और स्मृतियां का खत्म हो जाना एक संस्कृति का खत्म हो जाना है। नई पीढ़ी को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए वह विनोद कुमार शुक्ला की बाणभट्ट

महाश्वेता देवी स्मरण : उनकी रचनाओं में मिथक और आख्यान

दूसरे सत्र में ग्लोबल गांव के देवता एवं गुंभी रुलाई के कोरस पुस्तक के लेखक एवं मशहूर साहित्यकार गणेंद्र ने आदिवासी समाज एवं बिरसा मुंडा को लेकर उनके लिखे उपन्यासों एवं पत्रों की चर्चा करते हुए कहा कि महाश्वेता देवी के अलावा थिरले ही कोई लेखक मिलते हैं जो सड़क पर भी उतरा हो और लेखन से भी जुड़ा हो। महाश्वेता देवी की पुस्तक जंगल के दायेदार एवं चौड़ी मुंडा के तीर की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि एक किताब किसी शहीद की यात्रा को कितना आगे ले जाती है यह सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने बताया कि इन पुस्तकों के बाद ही बिरसा मुंडा एवं आदिवासी समुदाय के सघर्षों का मूल्यांकन राष्ट्रीय स्तर पर सही तरीके से हो सका। उन्होंने पलामू में बंधुआ मजदूर की लड़ाई लंबे समय तक की। महाश्वेता देवी आदिवासी समुदाय का सूक्ष्म पर्यवेक्षण इसलिए कर सकी क्योंकि उन्होंने देर सारा समय इस समुदाय के साथ बिताया। कई प्रसंगों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासियों के आंदोलन का तरीका व्यक्तिवादी नहीं होती, समुदायिक होती है। उन्होंने युवाओं को आह्वान किया कि यदि आदिवासी समाज को समझना है तो महाश्वेता देवी की रचनाओं को जरूर पढ़ें।

करतल ध्वनि के रूप में सत्रांत तक गुंजाता रहा।

पाथेर पांचाली पर भी हुई बात तीसरा सत्र- एक जंगल हुआ करता था- बियांड द जंग : ई-बुक- सत्र में पक्षी विज्ञानी विक्रम ग्रेवाल और युवा रचनाकार, विशेषज्ञ रज्ज काजामी की बातचीत कर रहा। विक्रम ग्रेवाल की चिंताएं देश में घटते जंगल, लुप्त होते पक्षी, विलुप्त होते पशु से लेकर उन्हें बचाने के उपाय तक एक लंबी चर्चा के रूप में आई। उन्होंने कहा लोगों को जंगलों और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील करना ही एकमात्र विकल्प है। इसी क्रम में जोर देते हुए कहते हैं कि झारखंड जैसे प्रदेश में बर्ड वाचिंग जैसे इको टूरिज्म को बढ़ावा देना जरूरी है ताकि लोग पशु, पक्षी, जंगल से जुड़ सकें और उनके रिहाइश के प्रति सजग और

BRIEF NEWS

विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

NALANDA : नालंदा जिले के राजगीर प्रखंड अंतर्गत खुदागंज थाना क्षेत्र के वैया गांव स्थित राय विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशन में नालन्दा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला जज गुरुचन्द्र सिंह महलहोत्रा व सचिव राजेश कुमार गौरव तथा अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति हिलसा के अध्यक्ष सह एडीजे आलोक कुमार पाण्डेय व सचिव सह एसडीजेएम शोभना स्वताकी के संयुक्त आदेश पर पैनल अधिवक्ता विजय कुमार एवं हिलसा विधिक सहायता केन्द्र व खुदागंज थाना में प्रतिनियुक्त पीएलवी आलोक कुमार के कुशल नेतृत्व में रविवार को बिहार पीड़ित मुआंजा विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सर्व प्रथम पीएलवी आलोक कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के गठन व उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्राधिकार द्वारा निः शुल्क विधिक सहायता सुविधाएं दी जा रही हैं जिसमें लोग अपनी समस्या को लेकर जा सकते हैं।

सर्दी का सितम जारी वायु प्रदूषण की स्थिति हुई खतरनाक

BHAGALPUR : जिले में सर्दी का सितम जारी है। रविवार को न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य तापमान से 6.0 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। वहीं शनिवार की रात और टिठरु गई। बीती रात में गलन कम रहा लेकिन रात का पारा 2.3 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया। वहीं सुबह में कहीं घना तो कहीं मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा। सुबह करीब साढ़े नौ बजे से सूरज बादलों की ओट से निकला तो दिन का मौसम साफ हो गया। दोपहर 12 बजेते-बजते लोगों को गुनगुनी गर्मी का पहसास घृण तले लगने लगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सब्जी के मौसम वैज्ञानिक डॉ. बरिन्द्र कुमार ने बताया कि अभी 14 जनवरी तक दिन का मौसम शुष्क तो रात में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। उधर धुंध के कारण धरती की सतह के पास हवा में धूलकण की मात्रा अधिक रही।

आईईएसएम की बैठक में पूर्व सैनिकों की समस्याओं पर चर्चा

BUXAR : रविवार को इंडियन एक्स-सर्विसमें मुवमेंट बक्सर का मासिक बैठक में मुंडेश्वरी अस्पताल परिसर में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर मेजर पी. के. पाण्डेय एवं जिलाध्यक्ष सुबेदार हरेंद्र तिवारी ने की, जबकि मंच संचालन जिला उपाध्यक्ष सुबेदार विद्या सागर चौबे ने किया। बैठक में जिले के सभी प्रखंडों से लगभग 150 पूर्व सैनिकों एवं वॉरिंगनाओं ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित सैनिकों ने एक स्वर में शहीद स्मारक पर युद्ध क्षेत्र में शहीद जिले के 16 वीरों के नाम शिलालेख पर अंकित कराए जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी अविभाषा सिंह, वन प्रमंडल पदाधिकारी भोजपुर प्रद्युम्न सिंह एवं बक्सर जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी सुरेश सिंह को बधाई दी।

तिल, गुड़ और लाई की खुशबू संग मकर संक्रांति का हो रहा स्वागत

AGENCY PATNA : सर्दियों की ठंडी हवा के बीच जब गलियों में तिलकुट की मीठी खुशबू फैलने लगती है, गुड़ की मिठास वातावरण में घुल जाती है और लाईझमुरही की खनक दुकानों पर सुनाई देने लगती है, तब यह संकेत होता है कि मकर संक्रांति अब दूर नहीं। शहर से लेकर गांव तक धीरे-धीरे पर्व का रंग चढ़ने लगता है। घरों में साफ-सफाई, बाजारों में चहल-पहल और रसोईघरों में पारंपरिक व्यंजनों की तैयारी इस पर्व के आगमन की घोषणा करती है।

मौसम के बदलाव के साथ नई ऊर्जा का पर्व : मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि

सर्दियों की ठिठुरन में पर्व की आहट, बाजारों से घरों तक छाई उत्सवी रौनक



सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व

मकर संक्रांति का सामाजिक महत्व भी कम नहीं है। यह पर्व आपसी मेल-मिलाप और रिश्तों में मिठास घोलने का अवसर प्रदान करता है। लोग एक-दूसरे के घर जाकर तिलकुट और गुड़ भेंट करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और बच्चों को मिठाइयां देते हैं।

बदलते दौर में भी जीवंत परंपरा

हालाकि, समय के साथ जीवनशैली में बदलाव आया है, लेकिन मकर संक्रांति की परंपराएं आज भी उतनी ही जीवंत हैं। आधुनिक मिठाइयों और फास्ट फूड के दौर में भी तिल, गुड़ और लाई का स्वाद लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। युवा पीढ़ी भी इन पारंपरिक पकवानों के महत्व को समझने लगी है।

कारीगरों की मेहनत और उम्मीदें

मकर संक्रांति कारीगरों के लिए खास समय होता है। तिलकुट बनाने वाले कारीगर बताते हैं कि वे महीनों पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। अच्छे तिल और शुद्ध गुड़ का चयन कर पारंपरिक तरीकों से तिलकुट तैयार किया जाता है। उनके लिए यह सिर्फ व्यवसाय नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही कला है।

भारतीय संस्कृति की वह जीवंत परंपरा है, जो मौसम के बदलाव के साथ जीवन में नई ऊर्जा और उमंग भर देती है। यह पर्व सूर्य के

उत्तरायण होने का प्रतीक है, जब दिन लंबे होने लगते हैं और शीत ऋतु की कठोरता धीरे-धीरे कम होने लगती है। इस बदलाव का

स्वागत देश के अलग-अलग हिस्सों में भिन्न रूपों में होता है, लेकिन उत्तर भारत विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर

प्रदेश में तिल, गुड़ और लाई का विशेष महत्व है। जैसे-जैसे मकर संक्रांति नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे बिहार के

बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन पर घने कोहरे के कारण हुआ दर्दनाक हादसा

खड़े कंटेनर से कार की हुई भीषण टक्कर में चार लोगों की गई जान

AGENCY PATNA : बिहार की राजधानी पटना के निकट बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन पर घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयावह था कि राहगीरों और स्थानीय लोगों को घायलों की मदद के लिए काफी मशकत करनी पड़ी। सबनीमा मुखिया प्रतिनिधि धर्मेश भारद्वाज ने बताया कि सड़क किनारे खड़ा एक कंटेनर टुक घने कोहरे के चलते दिखाई नहीं दे रहा था। तेज रफ्तार से आ रही एक स्कॉर्पियो पहले इस कंटेनर से टकराई, जिसके बाद पीछे से आ रही अन्य गाड़ियां भी आपस में भिड़ गईं। स्कॉर्पियो कंटेनर में इस कदर घुस गई कि उसमें सवार चारों लोग बुरी तरह फंस गए। हादसे की चपेट में आने वाली गाड़ियों में से एक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के सदस्य शामिल थे, जिनमें पिता और बेटी की मौत सबसे दर्दनाक तरीके से हुई है। गाड़ी में फंसे शवों को निकालने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास किए। लगभग आधे घंटे



सड़क सुरक्षा पर सवाल

यह हादसा बिहार में सर्दियों के मौसम में घने कोहरे के कारण होने वाले लगातार दुर्घटनाओं की कड़ी में एक और उदाहरण है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मौसम में कम स्पीड से वाहन चलाना, फॉग लाइट का इस्तेमाल और सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी है। प्रशासन से अपील की जा रही है कि फोरलेन जैसे प्रमुख मार्गों पर कोहरे के दौरान विशेष सतर्कता और साइनेज बोर्ड लगाए जाएं ताकि ऐसी त्रासदियां रोकੀ जा सकें।

तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो पहले कंटेनर से टकराई, उसके बाद पीछे से आ रही अन्य गाड़ियां भी आपस में भिड़ गईं

पुलिस ने कब्जे में लिए शव

अथमलगोला थाना के एसएसआई अंजनी कुमार ने बताया कि पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई थी। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने चारों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़ भेज दिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसा पूरी तरह घने कोहरे के कारण हुआ। मृतकों की पहचान और आगे की जांच जारी है।

तक जाम लगा रहा और बाद में एनएच की क्रेन की मदद से

क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे किया गया। एक मामले में गैस

कटर की सहायता से शव बाहर निकाले गए, जिसमें एक बेटी का

एक कंटेनर खराब होने के कारण सड़क पर साइड में लगा हुआ था। कोहरे के कारण एक कार जो बांका से फरीदीबाद जा रहा रही था वो टकरा गई। पिता और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई और दो लोग घायल हो गये। दूसरी कार भी पीछे से आकर टकरा गई, जिसमें और दो लोग घायल हो गये।

-धर्मेश भारद्वाज, मुखिया प्रतिनिधि सबनीमा

एक खड़ी कंटेनर में कार घुस गई, जिससे मौके पर दो लोगों की मौत हो गई। उसके बाद पीछे से आ रही एक और कार इससे जाकर टकरा गई। जिससे और दो लोग घायल हो गए।

-अंजनी कुमार, एसएसआई, अथमलगोला थाना

सिर अलग हो गया था। हादसे के तुरंत बाद फोरलेन पर भारी जाम लग गया और गाड़ियों की एक किलोमीटर लंबी लाइन खड़ी हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से आधे घंटे की मशकत के बाद एक लेन बहाल की गई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त गाड़ियों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारु किया, जिससे स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हुई।

मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस ने रखा एक दिन का उपवास

AGENCY BHAGALPUR : मनरेगा योजना को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारतइजी राम जी योजना किए जाने के प्रस्ताव पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। सरकार की ओर से प्रस्ताव है कि योजना के तहत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 किया जाए, साथ ही साप्ताहिक भुगतान व्यवस्था लागू की जाए, ताकि ग्रामीण विकास और आजीविका सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। हालांकि यह प्रस्ताव अभी संसद में पेश किया गया है और इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। इसी मुद्दे को लेकर रविवार को भागलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन



किया। भागलपुर स्टेशन चौक स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर गोलंबर के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम आयोजित कर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष परवेज जमाल ने कहा कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं और उनके नाम से चलने वाली मनरेगा योजना का नाम बदलना गांधीजी के विचारों और ग्रामीण गरीबों के अधिकारों का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार इस योजना के जरिए मजदूरों के हक को कमजोर कर रही है।

कोर्ट के आदेश से पांच दुकानों पर चला बुलडोजर

AGENCY BHAGALPUR : भागलपुर में 27 साल से अदालतों के गलियारों में घूम रहा भूमि विवाद आखिरकार जमीन पर उतर आया। महात्मा गांधी रोड स्थित सिविल सर्जन कम्पाउंड में रविवार को जैसे ही प्रशासन का पीला पंजा गरजा पूरे इलाके में हलचल मच गई। कोर्ट के आदेश के बाद एक साथ दो बुलडोजर चले और देखते ही देखते पांच दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। पीला पंजा चलते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कोई शटर गिरता नजर आया तो कोई आनन-फानन में सामान समेटता दिखा। चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कार्रवाई के दौरान कोर्ट के नाजिर, अधिवक्ता और दंडाधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते रहे। हालांकि कुछ ही देर बाद घटनास्थल पर सदर



अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार पहुंचे। स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने बड़ा फैसला लिया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को फिलहाल 15 दिनों के लिए रोक दिया। सदर एसडीओ विकास कुमार ने बताया कि प्रशासन को सूचना मिली थी कि कार्रवाई जारी रहने से विधिव्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्थायी रोक लगाई गई है।

उन्होंने साफ किया कि आगे न्यायालय से जो भी आदेश आएगा उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि यह विवाद वर्ष 1998 से न्यायालय में चल रहा था। स्थानीय महिला आशा देवी ने वर्ष 2011 में निचली अदालत से केस जीता था और 2024 में अपील में भी उनके पक्ष में फैसला आया। इसके बाद कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। जिसके अनुपालन में यह कार्रवाई शुरू की गई।

लायंस क्लब ने हंगर सेवा सप्ताह के तहत 200 लोगों को कराया भोजन

SARAN : छपरा लायंस क्लब टाउन द्वारा सेवा परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 'हंगर सेवा सप्ताह' का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत क्लब के सदस्यों ने छपरा कचहरी स्टेशन परिसर में शिविर लगाकर लगभग दो सौ से अधिक असहाय, वृद्ध एवं जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन का वितरण किया। क्लब के सचिव मनीष कुमार ने बताया कि स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों और स्थानीय जरूरतमंदों ने उत्साहपूर्वक इस सेवा का लाभ उठाया। क्लब के अध्यक्ष अभिषेक किशोर ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा, 'हंगर सेवा सप्ताह का मुख्य उद्देश्य समाज में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इस संदेश को प्रसारित करना है।

बाजारों की रौनक बढ़ती जा रही है। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर तिलकुट और गुड़ की दुकानों की कतारें सज गई हैं। पारंपरिक कारीगर दिन-रात मेहनत कर ताजे तिलकुट तैयार कर रहे हैं। कहीं गोल तिलकुट लोगों को लुभा रहा है, तो कहीं गजक और तिल की चिककी की खुशबू ग्राहकों को अपनी ओर खींच रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस वर्ष भी तिल और गुड़ से बनी मिठाइयों की मांग अच्छी बनी हुई है, क्योंकि त्यंजण आज भी पारंपरिक स्वाद से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। लाई और मुरही की दुकानों पर बच्चों की भीड़ देखते ही बनती है। रंग-बिरंगे

पैकेटों में सजी लाई त्योहार की मिठास को और बढ़ा देती है। ग्रामीण इलाकों में आज भी घर-घर में लाई बनाने की परंपरा कायम है, जहां महिलाएं सामूहिक रूप से लाई तैयार करती हैं।

घरों में शुरू हुई त्योहार की तैयारी : मकर संक्रांति के आगमन के साथ ही घरों का माहौल भी उत्सवमय हो जाता है। रसोईघरों में तिलकुट, तिल-गुड़ के लड्डू, दही-चूड़ा और अन्य पारंपरिक व्यंजनों की तैयारी शुरू हो जाती है। परिवार के सभी सदस्य इस प्रक्रिया में शामिल होकर पर्व की खुशियों को दोगुना कर देते हैं।

NEWS

BOX

अत्यधिक ठंड को देखते हुए कक्षा 5 तक के स्कूल कल तक बंद

AGENCY PATNA : पटना जिले में लगातार गिरते तापमान और बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा कदम उठाया है। यह



आदेश पटना जिले में 12 जनवरी 2026 से लागू होकर 13 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह आदेश प्री-स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी सामान्य रूप से लागू होगा। जिला प्रशासन के अनुसार, यह निर्णय छोटे बच्चों को ठंड से होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि, कक्षा-6 और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह बंद नहीं की गई हैं। इन कक्षाओं का संचालन अब संशोधित समय-सारणी के तहत पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे के बीच किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश के अनुरूप समय-सारणी में आवश्यक बदलाव सुनिश्चित करें। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी अथवा उनसे संबंधित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगी तथा उनका संचालन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा।

विकसित भारत की मजबूत नींव है 'जी राम जी' योजना : शैलेंद्र

AGENCY BHAGALPUR : बिहपुर प्रखंड के एनडीए कार्यालय बिहपुर में रविवार को विकसित भारत रोजगार आर आजीविका मिशन की प्रेस वार्ता किया। इस मौके पर बिहपुर विस के भाजपा विधायक डॉ. शैलेंद्र भी उपस्थित थे। वहीं प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए नवगठित भाजपा जिला मंत्री सह नवगठित पुलिस जिला वीबी जी राम जी के प्रभारी प्रवेश रूप ने कहा कि प्रति ग्रामीण परिवार को मिलने वाले अस्थायी मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी को साल में सौ से बढ़ाकर 25 दिन कर देता है। किसानों की वित्ताओं को दूर करने के लिए राज्यों को बुआई और कटाई के मौसम के दौरान 60 दिनों तक कृषि कार्य विराम घोषित करने का अधिकार है। श्री रूप ने कहा कि यह विराम सलाना 125 दिनों की कानूनी गारंटी को कम नहीं करता है। इससे किसानों और श्रमिक हितों में संतुलन बना रहेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने यूपीए शासन के दौरान मनरेगा से इसमें चार गुणा अधिक बजट दिया। इसके बावजूद मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया। मनरेगा में मजदूरों के बदले ठेकेदार और मशीन काम करता था। इसको लेकर 23 राज्यों में जांच के बाद जी राम जी के लाया गया है।

पुलिस ने 20 लाख मूल्य के गांजे की फसल को किया नष्ट, एक गिरफ्तार

AGENCY NAVADA : नवादा जिले के सीतामढ़ी थाने के शाहबाजपुर सराय गांव में रविवार को उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़े कार्रवाई को अंजाम देते हुए लगभग 20 लाख रुपए मूल्य की गांजे की फसल को नष्ट कर दिया है। एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसने बड़े पैमाने पर



गांजे की खेती करने की बात भी स्वीकार की। इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में फल-फूल रही अवैध मादक पदार्थों की खेती पर रोक लगाना था। सूचना की पुष्टि के बाद गठित विशेष टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छात्रमारी की और मौके पर अवैध रूप से उगाए गए गांजा के पौधों की पहचान की। कार्रवाई के दौरान टीम ने खेतों में लगे गांजा के पौधों की कटाई कर उन्हें विधिवत रूप से विनष्ट किया। उत्पाद विभाग की इस सख्त कार्रवाई से इलाके में अवैध नशा कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। अभियान के क्रम में मौके से गांजे कारोबारी बबलू सिंह को गिरफ्तार किया गया। जिसे आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत हिरासत में लेकर पुष्काल की जा रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्र ने बताया कि मादक पदार्थों की अवैध खेती, तस्करों एवं सेवन के खिलाफ विभाग लगातार अभियान चला रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे अवैध कार्यों में सहभागिता किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगी और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

जदयू ने चलाया सदस्यता अभियान बूथ स्तर तक सदस्य बनाने का लक्ष्य

AGENCY NAVADA : नवादा सदर विधायक विभा देवी के नेतृत्व में जनता दल (यूनाइटेड) का सदस्यता अभियान रविवार को भी चलाया गया। नवादा प्रखंड जदयू कार्यकर्ताओं की बैठक विधायक के कार्यालय परिसर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष नवल चौहान ने की। जबकि जिलाध्यक्ष मुकेश विद्याधी ने उपस्थित कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। विधायक विभा देवी ने स्वयं प्रेरणादायक करते हुए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि जिस तरह से चुनाव में आलोगों ने निष्ठापूर्ण भागीदारी निभाई है उसी तरह सदस्यता अभियान को भी गंभीरता से लेते हुए सफल बनाया है। उन्होंने सदस्यता अभियान के महत्व को निरर्थित करते हुए कहा कि नवादा के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी हम सबको को उठानी है। लिहाजा हम सबको माननीय मुख्यमंत्री के आदर्शों और सिद्धांतों को आमसत करके हुए अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी है। जिलाध्यक्ष मुकेश विद्याधी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि प्रत्येक सक्षम कार्यकर्ता ही पार्टी के विभिन्न पदों पर रहकर जनसेवा का वास्तविक भागीदार बन सकते हैं। उन्होंने दोहराया कि जिले में तीन लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। पार्टी के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता जयशंकर चंद्रवंशी ने कहा कि जिस तरह हम सबने माननीय विधायक को भारी मंती से जितया है उसी तरह अपनी चढ़ती एकता का परिचय देते हुए सदस्यता के निर्धारित लक्ष्य को भी पूरा करेंगे।

कार्यक्रम

सीएम के निरीक्षण के बाद जगी उम्मीद, गोलघर पर जल्द चढ़ सकेंगे आम लोग

गोलघर परिसर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया भ्रमण

AGENCY PATNA : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को ऐतिहासिक गोलघर परिसर का भ्रमण कर वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने गोलघर परिसर पार्क, गोलघर के स्ट्रक्चर की स्थिति, लाइट एंड साउंड एवं लेजर शो आदि का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि गोलघर एक ऐतिहासिक धरोहर है, काफी संख्या में लोग इसे देखने आते हैं। गोलघर परिसर के सौंदर्यीकरण एवं इसके रखरखाव को अच्छे ढंग से कराएं ताकि यह देखने में मनोरम लगे। वर्ष 2013 में यहां शुरू किए गए लाइट एंड साउंड तथा लेजर शो



का नियमित रूप से संचालन हो, इससे लोगों इतिहास के संबंध में जनकारी प्राप्त होगी।

जीर्णोद्धार के कारण था बंद

पटना आने वाले लोग एक बार गोलघर को जरूर घूमने जाते हैं, लेकिन लंबे समय से गोलघर आम लोगों के लिए बंद पड़ा हुआ है। 2017 से गोलघर के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ था। कोविड के कारण भी इसके जीर्णोद्धार कार्य पर असर पड़ा। बीच में कुछ समय के लिए खुला भी लेकिन गोलघर को आकर्षक बनाने के नाम पर बंद कर दिया गया।

नहीं थी चढ़ने की इजाजत

गोलघर में लाइटिंग के साथ अन्य सुविधाओं को मुख्यमंत्री के निर्देश पर हैं 2013 से विकसित किया गया है। गोलघर देखने के साथ लोग इसका भी आनंद लेते थे, लेकिन लंबे समय से गोलघर पर चढ़ने की अनुमति नहीं थी।

कहा कि गोलघर वास्तु कला का एक अदभुत नमूना है इसलिए इसके स्ट्रक्चर के रखरखाव का विशेष रूप से ख्याल रखें ताकि इसे और बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से गोलघर के बारे में जानकारी ली। स्ट्रक्चर की स्थिति, लाइट एंड साउंड एवं लेजर शो के बारे में भी जानकारी ली और उन्हें दिशा निर्देश दिया। राजधानी पटना का गोलघर ब्रिटिश काल में बनाया गया था। कैप्टन जॉन गार्स्टिन ने 1770 के भयानक अकाल के बाद ब्रिटिश सेना के लिए 1786 में बनवाया था, जिसका निर्माण कार्य 20 जुलाई 1786 को पूरा हुआ था।

इसके लिए यहां डिस्पले बोर्ड भी लगाकर प्रदर्शित करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने

मानवता के मुखौटे में छिपा एजेंडा

आज वैश्विक मंच पर कुछ ऐसे समूह सक्रिय हैं, जो स्वयं को मानवाधिकारों का ठेकेदार और उत्पीड़ितों की आवाज बनाने में पीछे नहीं रहते। लंदन, टोरंटो और यूरोप के कई शहरों में सक्रिय खालिस्तानी समर्थक इसी श्रेणी में आते हैं। ये लोग भारत में कथित अल्पसंख्यक अत्याचारों के नाम पर प्रदर्शन करते हैं, नारे लगाते हैं और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही लोग जब बांग्लादेश, पाकिस्तान या अन्य इस्लामी देशों में हिंदुओं पर हो रहे संगठित अत्याचारों, नरसंहार, बलात्कार और मंदिर विध्वंस की घटनाओं का सामना करते हैं तो उनकी तथाकथित मानवता अचानक मौन धारण कर लेती है। यह मौन सामान्य नहीं है। यह चर्यनित संवेदना का परिणाम है, जो किसी नैतिक मूल्य से नहीं उपजा है, यह एक सुनियोजित राजनीतिक एजेंडे से संचालित है। कई बार स्थिति इससे भी आगे बढ़ जाती है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध के बजाय ये समूह जय बांग्लादेश जैसे नारे लगाते दिखाई देते हैं। यह आचरण स्पष्ट करता है कि इनके लिए मानवाधिकार सार्वभौमिक मूल्य नहीं, बल्कि राजनीतिक औजार मात्र है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि लंदन और पश्चिमी देशों में सक्रिय अधिकांश खालिस्तान समर्थक संगठन मानवीय नितियों के लिए खड़े न होकर भारत-विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से खड़े किए गए हैं। इनमें से अनेक लोग अवैध प्रवासी हैं, कुछ स्थानीय वेलफेयर योजनाओं पर निर्भर हैं और कुछ का संबंध छोटे आपराधिक गिरोहों, ड्रग चालित और भारत-विरोधी धन-शोधन नेटवर्क से जुड़ा रहा है। जब आर्थिक आधार ही संदिग्ध और अंधेरे स्रोतों से आता हो, तब विचारधारा और राजनीतिक रुख भी उसी दिशा में ढल जाता है। ऐसे में इनकी राजनीति को मानवाधिकार आंदोलन कहना सत्य का अपमान होगा। यह वस्तुतः फंडिंग आधारित, एजेंडा चालित और भारत-विरोधी राजनीति है। इस पूरे तंत्र के पीछे गहरा और खतरनाक गठजोड़ काम करता है, जिसे कई सुरक्षा विशेषणों में आईएसआई-खालिस्तानी-इस्लामिस्ट गठजोड़ के रूप में चिह्नित किया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कई समय से भारत को हजार घावों से कमजोर करने की रणनीति पर काम करती रही है। इसी रणनीति के अंतर्गत खालिस्तानी अलगाववादियों को वित्तीय सहायता, प्रचार संसाधन और अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराए जाते हैं। लंदन और यूरोप में सक्रिय कुछ इस्लामी करुणपंथी नेटवर्क और संगठन उन्हें लॉजिस्टिक सहायता देते हैं। इन सभी का साझा उद्देश्य एक ही है- भारत को वैश्विक मंच पर बदनाम करना और उसकी सामाजिक-सांस्कृतिक एकता पर प्रश्नचिह्न लगाना। ऐसे गठबंधन के लिए बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार कोई मुद्दा नहीं बनते, क्योंकि वे इनके विक्रिम बनाम पप्टेरिट नैरेटिव में फिट नहीं बैठते। इनके वैचारिक ढांचे में मुसलमान सदैव पीड़ित और भारत अथवा हिन्दू समाज सदैव उत्पीड़क के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यदि ये लोग बांग्लादेश में हिंदू लड़कियों पर हो रहे अत्याचार, परिवारों के कल्लेआम और मंदिर विध्वंस की निंदा करेंगे, तो यह पूरा झूठा नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा और इनके इस्लामी सहयोगी उनसे दूरी बना लेंगे। यही कारण है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं के गांव जलाए जाते हैं, महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार होता है और सैकड़ों परिवार पलायन को मजबूर होते हैं, तब ये तथाकथित मानवाधिकार रक्षक चुप रहते हैं। यह चुप्पी उनकी सच्चाई उजागर करती है। उनके लिए मानवाधिकार नहीं, बल्कि राजनीतिक गठबंधन और फंडिंग अधिक महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों जैसे एसओएएस लंदन, हार्वर्ड व टोरंटो यूनिवर्सिटी में वर्षों से लेफ्ट-इस्लामिस्ट-खालिस्तानी गठजोड़ सक्रिय देखा जा सकता है। इनके सेमिनार, शोधपत्र और अभियानों का केंद्रीय विचार यही होता है कि भारत एक दमनकारी राष्ट्र है, मुसलमान हमेशा पीड़ित हैं और खालिस्तानी अलगाववादी उनके स्वाभाविक सहयोगी हैं। इस वैचारिक पूर्वाग्रह के कारण बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार इनके लिए असुविधाजनक सत्य बन जाते हैं। इसलिए या तो इन घटनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर इन पर बोलने वालों को दक्षिणपंथी और नफरत फैलाने वाला बताकर चुप कराने की कोशिश की जाती है। लंदन की सड़कों पर जय बांग्लादेश के नारे लगाना इसी नैरेटिव हाइजैकिंग का हिस्सा है। इसका उद्देश्य पीड़ित हिंदू परिवारों की पीड़ा को दबाकर भारत-विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाना है। यह व्यवहार बताता है कि इनकी राजनीति नैतिकक, करुणा या मानवता पर आधारित नहीं है, बल्कि धन, गठबंधन और भारत-विरोधी सोच पर टिकी हुई है। ऐसे में हम सभी को स्पष्ट रूप से समझना होगा कि लंदन और अन्य पश्चिमी देशों में सक्रिय खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियां किसी स्वतःस्फूर्त जनआंदोलन का परिणाम नहीं हैं। यह एक सुनियोजित, फंडेड और राजनीतिक रूप से इंजीनियर किया गया प्रयास है, जिसमें मानवता केवल मुखौटा है। वास्तविक उद्देश्य भारत को बदनाम करना, उसकी सामाजिक एकता को कमजोर करना और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसके विरुद्ध वातावरण बनाना है। अतः इन परिस्थितियों में भारत और विश्व के विवेकशील नागरिकों का दायित्व है कि वे मानवाधिकार के नाम पर चल रहे इस पाखंड को पहचानें और सच्चे पीड़ितों विशेषकर बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित हिंदुओं की आवाज को मजबूती से उठाएं।

ANALYSIS



श्याम किशोर चौधरी

रांची में तीन दर्जन से अधिक मुहल्लों में दूषित जल की आपूर्ति की शिकायतें मिल रही हैं। दो महीने में 127 शिकायतें नगर निगम में और पेयजल स्वच्छता प्रमंडल में भी 50 से अधिक शिकायतें दर्ज करायी जा चुकी हैं। इसके बावजूद कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही एक दूसरी खबर यह भी है कि राजधानी रांची के बीचोंबीच बह रही हरमू नदी के किनारे-किनारे एक तो अतिक्रमण है, दूसरे उसे नदी न मानकर नागरिक कचरा पेटी समझ रहे हैं। वह कूड़े-कचरों से पटी पड़ी है। यह स्थिति तब है, जबकि 2015 में इस नदी को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार ने 85 करोड़ रुपये बहा दिए थे। चार दिन की चांदनी रही, आगे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक बार फिर से उसे स्वच्छ बनाने की नीयत से नगर निगम सफाई अभियान चला रहा है। राजधानी के बीचोंबीच मल-मूत्र, घरों की गंदगी तथा प्लास्टिक आदि से लदी-फदी नदी बह रही है, अब्बल तो उसका प्रवाह मंद पड़ा हुआ है, तो जाहिर है कि इसका असर भूगर्भीय जल पर भी पड़ रहा है। जो लोग उसके आसपास बोरिंग आदि से भूगर्भीय जल निकालकर सेवन कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पर निश्चय ही बुरा असर पड़ रहा है। बरसात में जब थोड़ा और दूषित-प्रदूषित पानी मिलने लगता है, पेट संबंधी बीमारियां बढ़ने लगती हैं, तब हम डॉक्टरों या

हाल ही एक खबर परंपरागत तरीके से आई। चूँकि ऐसी खबरें अक्सर आती रहती हैं, इसलिए इन्हें हम रोजमर्रा की घटनाएं मान लेते हैं। दरहकीकत यह बहुत गंभीर विषय है। खबर यही थी कि रांची में तीन दर्जन से अधिक मुहल्लों में दूषित जल की आपूर्ति की शिकायतें मिल रही हैं। दो महीने में 127 शिकायतें नगर निगम में और पेयजल स्वच्छता प्रमंडल में भी 50 से अधिक शिकायतें दर्ज करायी जा चुकी हैं। इसके बावजूद कोई सुधार नहीं हो पा रहा है।

इसके साथ ही एक दूसरी खबर यह भी है कि राजधानी रांची के बीचोंबीच बह रही हरमू नदी के किनारे-किनारे एक तो अतिक्रमण है, दूसरे उसे नदी न मानकर नागरिक कचरा पेटी समझ रहे हैं। वह कूड़े-कचरों से पटी पड़ी है। यह स्थिति तब है, जबकि 2015 में इस नदी को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार ने 85 करोड़ रुपये बहा दिए थे। चार दिन की चांदनी रही, आगे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक बार फिर से उसे स्वच्छ बनाने की नीयत से नगर निगम सफाई अभियान चला रहा है। राजधानी के बीचोंबीच मल-मूत्र, घरों की गंदगी तथा प्लास्टिक आदि से लदी-फदी नदी बह रही है, अब्बल तो उसका प्रवाह मंद पड़ा हुआ है, तो जाहिर है कि इसका असर भूगर्भीय जल पर भी पड़ रहा है। जो लोग उसके आसपास बोरिंग आदि से भूगर्भीय जल निकालकर सेवन कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पर निश्चय ही बुरा असर पड़ रहा है।

बरसात में जब थोड़ा और दूषित-प्रदूषित पानी मिलने लगता है, पेट संबंधी बीमारियां बढ़ने लगती हैं, तब हम डॉक्टरों या



अस्पतालों की आय बढ़ाने में खुद को झोंक देते हैं। उन दिनों क्या सरकारी, क्या निजी अस्पताल और क्लिनिकों में मरीजों की भरमार हो जाती है। जो जीवित बच जाते हैं, वे फिर पहले जैसा रम जाते हैं। जो गुजर जाते हैं, उनके लिए रो-धोकर शांत हो लेते हैं। यह स्थिति अकेले रांची या किसी एक शहर की नहीं, अपितु पूरे राज्य की है। अपने गांव-गिरांव में तो ढाढ़ी-चुआं का पानी ही काम आता रहा है। हमारी सरकारें अब तक पानी पर न जाने कितने करोड़ बहा-डुबा चुकीं, लेकिन हर किसी को स्वच्छ पानी सपना ही बना हुआ है।

यह कितना गंभीर सवाल है, इसे झारखंड हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा 6 जनवरी 2026 को जारी क्षोभ से समझा जा सकता है। दो अधिवक्ताओं- खुशबू कटारूका और शुभम कटारूका द्वारा दाखिल पीआईएल पर शीर्ष अदालत ने सरकार को जवाब तलब करते

हुए निर्देश दिया कि वह अपना स्पष्ट और तथ्यपरक जवाब दाखिल करें। अदालत ने साफ-साफ कहा कि पेयजल का मुद्दा सीधे तौर पर आम जनजीवन और स्वास्थ्य से संबंधित है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोताही और लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। झारखंड के विपरीत हाल की दो खबरों ने पूरे देश का ध्यान खींचा। पहली तो यही कि मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में दूषित जल के सेवन से 15 से अधिक लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग अस्पताल दाखिल हुए। यह वाकया बीते दिसंबर के अंतिम सप्ताह का है। लगे हाथ तीन जनवरी को खबर आ गई कि गुजरात के गांधीनगर में दूषित पानी का कहर देखने को मिल रहा है। यहां के सेक्टर 24, 28 और आदिवाड़ा इलाकों में पीने का पानी दूषित होने के चलते टायफाइड के 100 से अधिक सैद्धिम मामले सामने आए। रिपोर्ट किए गए 113 मामलों में से 19 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी को इलाज

के लिए गांधीनगर सिविल अस्पताल और सेक्टर 24 और 29 के स्वास्थ्य केंद्रों में दाखिल कराया गया। गांधीनगर में कम से कम सात स्थानों पर रिसाव के कारण पीने के पानी में सीवेज मिल गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह घटना 257 करोड़ रुपये के निवेश से शुरू हुई चौबीसों घंटे जलापूर्ति परियोजना के बाद हुई है, जिसके तहत सीवर लाइनों के पास नई पानी की पाइपलाइनें बिछाई गई थीं।

नरेंद्र मोदी ने पहली मर्तवा प्रधानमंत्री बनने के बाद देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया था। तब बहुत सारे लोग झाड़ू लेकर गली-गली उतर पड़े थे। लगता था कि अब गंदगी के दर्शन ही नहीं होंगे। उसी सिलसिले में शहरों की स्वच्छता रैंकिंग में नंबर वन है। गांधीनगर एक तो चंडीगढ़ के बाद विकसित की गई दूसरी प्लांड सिटी है, दूसरी बात यह कि झारखंड को भी इंदौर जैसे हादसे का इंतजार है, यह सवाल बहुत मौजू है।

चिनाब पर भारत ने उठाया निर्णायक कदम

दक्षिण एशिया की राजनीति में आज जल, प्राकृतिक संसाधन से अधिक रणनीति, संप्रभुता और सुरक्षा का अहम हथियार बन चुका है। चिनाब नदी पर भारत द्वारा उठाया गया ताजा कदम इसी बदले हुए भू-राजनीतिक यथार्थ का सशक्त उदाहरण है। दुलहस्ती हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को जैसे ही भारत सरकार की पर्यावरणीय समिति से मंजूरी मिली, इस फैसले की गूंज सरहद पार पाकिस्तान तक सुनाई देने लगी। वहां की राजनीति में खलबली मच गई, आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए और एक बार फिर सिंधु जल समझौता चर्चा के केंद्र में आ गया है। भारत के लिए यह ऊर्जा आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय हित का सवाल है, जबकि पाकिस्तान इसे अपने अस्तित्व और जल अधिकारों से जोड़कर देख रहा है। भारत सरकार की पर्यावरण विभाग की विशेषज्ञ समिति ने 27 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर स्थित दुलहस्ती हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के

स्टेज-2 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की है। वस्तुतः यह मंजूरी मिलते ही पाकिस्तान की सियासत में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की वरिष्ठ सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शेरी रहमान ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत पर पानी को हथियार बनाने का संगीन आरोप लगाया। उनके अनुसार, यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है और अंतरराष्ट्रीय समझौते की भावना के विरुद्ध है। शेरी रहमान का दावा है कि साल 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुए इस समझौते के तहत पाकिस्तान को चिनाब, झेलम और सिंधु नदियों के जल पर अधिकार प्राप्त हैं, जबकि भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। रहमान का आरोप है कि भारत ने एकतरफा तरीके से सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है, जो न तो कानूनी है और न ही नैतिक रूप से स्वीकार्य।

पाकिस्तान को आपत्ति केवल दुलहस्ती परियोजना तक सीमित नहीं है। शेरी रहमान ने भारत द्वारा चिनाब घाटी में संचालित या प्रस्तावित कई अन्य परियोजनाओं को भी विवादस्पद करार दिया। उन्होंने सावलकोट, रेटल, बडसर, पाकल डुल, क्वार, कीरू और किराई जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि भारत सुनियोजित ढंग से इन सभी पर काम तेज कर रहा है। पाकिस्तान का तर्क है कि इन परियोजनाओं के कारण भविष्य में उसके हिस्से के पानी में कटौती हो सकती है, जिससे उसकी कृषि, खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर भारत का दृष्टिकोण इससे एकदम अलग और स्पष्ट है। भारत बार-बार यह दोहराता रहा है कि सिंधु जल समझौते में उसे पश्चिमी नदियों पर वैध अधिकार प्राप्त हैं। भारत इन नदियों पर न ऑफ द रिवर परियोजनाएं स्थापित कर सकता है। दुलहस्ती परियोजना इसी श्रेणी

में आती है, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण से अधिक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन है। इस पूरे घटनाक्रम को हालिया सुरक्षा परिदृश्य से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसी वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने भारत-पाक संबंधों में पहले से मौजूद तनाव को और गहरा कर दिया। इस हमले में 22 निर्दोष पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या कर दी गई थी। जांच एजेंसियों की रिपोर्टों में पाकिस्तानी आतंकवादियों की संलिप्तता सामने आने के बाद भारत सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया। इसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का फैसला लिया और पाकिस्तान के साथ जल प्रवाह से जुड़ी तकनीकी जानकारियां साझा करनी बंद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संदर्भ में कई बार दो टूक शब्दों में कह चुके हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। यह कथन अब केवल

राजनीतिक बयान नहीं माना जाना चाहिए, यह भारत की नई रणनीतिक सोच का प्रतीक बन चुका है। भारत का मानना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित आतंकवाद पर ठोस और निर्णायक कार्रवाई नहीं करता, तब तक किसी भी प्रकार के सहयोग या संवाद का आधार नहीं बन सकता। इसके साथ एक तथ्य यह भी है कि दुलहस्ती हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के तहत लगभग 260 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन की योजना है। इससे जम्मू-कश्मीर में ऊर्जा उपलब्धता को मजबूती मिलेगी और देश की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह परियोजना पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ ही स्थानीय विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को भी गति देने वाली है। इसके साथ ही भारत सरकार चिनाब नदी पर प्रस्तावित सावलकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर भी गंभीर

तैयारी कर रही है। करीब 1856 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना पूरी होने पर उत्तरी भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में शुमार होगी। भारत का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि जम्मू-कश्मीर जैसे पर्वतीय क्षेत्र जलविद्युत की अपार संभावनाओं से भरपूर हैं और इसका उपयोग राष्ट्रीय हित, ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के लिए किया जाना चाहिए। अतः चिनाब नदी पर भारत का यह कदम तकनीकी या ऊर्जा परियोजना भर नहीं है, यह बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों का संकेतक है। पाकिस्तान की बौखलाहट और आरोपों के बावजूद भारत यह संदेश देने में सफल रहा है कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और संप्रभु अधिकारों पर कोई समझौता नहीं होगा। फिलहाल मोदी सरकार अपने कहे पर अडिग नजर आ रही है। निश्चित ही इस निर्णय से प्रत्येक भारतवासी अपनी सरकार पर गौरव महसूस कर सकता है।

घरेलू बाजार, कर सुधार और एफटीए आर्थिक विकास को देंगे गति

नए साल 2026 की आर्थिक संभावनाओं पर प्रकाशित विभिन्न वैश्विक आर्थिक संगठनों की रिपोर्टों के अनुसार नववर्ष भारत के लिए बेहतर आर्थिक संभावनाओं वाला होगा। केयर एज रेटिंस के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था सात प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। ऐक्सिस बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आगामी वर्ष में भारत की विकास दर 7.5 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर पहुंचती दिख सकती है। जहां भारत वर्ष 2025 में 4.18 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिकी बन गया है। नए साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उंगर पर आगे बढ़ेगा। वैश्विक निवेश फर्म इन्वेसको का कहना है कि इस साल भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति कायम रखेगा। हालांकि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत को आर्थिक और वित्तीय सुधारों को गति भी देनी होगी। नए वर्ष में घरेलू बाजार की मजबूती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत आधार बनी रहेगी। इस दौरान भारत का घरेलू बाजार 10 प्रतिशत से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ेगा और इस तेज गति से वर्ष 2030 तक भारत का घरेलू बाजार लगभग 237 अरब डालर की ऊंचाई पर

पहुंच सकता है। 2026 में महंगाई घटने, टैक्स सुधार और ब्याज दर में कमी से घरेलू बाजार को रफ्तार से बढ़ने के आधार मिलेंगे। रिजर्व बैंक का कहना है कि 2026 में महंगाई में नरमी बनी रहेगी। गत वर्ष जीएसटी की दरों में सुधारों की जो पहलू शुरू हुई है, उसके फल इस साल और व्यापक रूप से मिलने शुरू होंगे। नए वर्ष में मनेरगा की जगह लागू वीबी-जी राम जी से भी ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। एक अप्रैल से लागू किया जाने वाला नया इनकम टैक्स कानून महज कुछ धाराओं के बदलाव ही नहीं, बल्कि पूरी टैक्स व्यवस्था के कायापलट के साथ आर्थिकी को आगे बढ़ाया है। इससे मध्यम वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इससे मांग बढ़ेगी और निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती का जो सिलसिला शुरू किया, उसके इस साल ही जारी रहने के ही आसार हैं। इससे भी मांग और खपत में तेजी आएगी। वैश्विक वित्तीय सलाहकार फर्म ग्लोबल वेल्थ मैनेजर की नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2026 खपत के स्तर में सुधार के मामले में भारत मजबूत आधार बनी रहेगी। इस दौरान भारत का घरेलू बाजार 10 प्रतिशत से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ेगा और इस तेज गति से वर्ष 2030 तक भारत का घरेलू बाजार लगभग 237 अरब डालर की ऊंचाई पर

पहुंच सकता है। 2026 में महंगाई घटने, टैक्स सुधार और ब्याज दर में कमी से घरेलू बाजार को रफ्तार से बढ़ने के आधार मिलेंगे। रिजर्व बैंक का कहना है कि 2026 में महंगाई में नरमी बनी रहेगी। गत वर्ष जीएसटी की दरों में सुधारों की जो पहलू शुरू हुई है, उसके फल इस साल और व्यापक रूप से मिलने शुरू होंगे। नए वर्ष में मनेरगा की जगह लागू वीबी-जी राम जी से भी ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। एक अप्रैल से लागू किया जाने वाला नया इनकम टैक्स कानून महज कुछ धाराओं के बदलाव ही नहीं, बल्कि पूरी टैक्स व्यवस्था के कायापलट के साथ आर्थिकी को आगे बढ़ाया है। इससे मध्यम वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इससे मांग बढ़ेगी और निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती का जो सिलसिला शुरू किया, उसके इस साल ही जारी रहने के ही आसार हैं। इससे भी मांग और खपत में तेजी आएगी। वैश्विक वित्तीय सलाहकार फर्म ग्लोबल वेल्थ मैनेजर की नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2026 खपत के स्तर में सुधार के मामले में भारत मजबूत आधार बनी रहेगी। इस दौरान भारत का घरेलू बाजार 10 प्रतिशत से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ेगा और इस तेज गति से वर्ष 2030 तक भारत का घरेलू बाजार लगभग 237 अरब डालर की ऊंचाई पर

पहुंच सकता है। 2026 में महंगाई घटने, टैक्स सुधार और ब्याज दर में कमी से घरेलू बाजार को रफ्तार से बढ़ने के आधार मिलेंगे। रिजर्व बैंक का कहना है कि 2026 में महंगाई में नरमी बनी रहेगी। गत वर्ष जीएसटी की दरों में सुधारों की जो पहलू शुरू हुई है, उसके फल इस साल और व्यापक रूप से मिलने शुरू होंगे। नए वर्ष में मनेरगा की जगह लागू वीबी-जी राम जी से भी ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। एक अप्रैल से लागू किया जाने वाला नया इनकम टैक्स कानून महज कुछ धाराओं के बदलाव ही नहीं, बल्कि पूरी टैक्स व्यवस्था के कायापलट के साथ आर्थिकी को आगे बढ़ाया है। इससे मध्यम वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इससे मांग बढ़ेगी और निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती का जो सिलसिला शुरू किया, उसके इस साल ही जारी रहने के ही आसार हैं। इससे भी मांग और खपत में तेजी आएगी। वैश्विक वित्तीय सलाहकार फर्म ग्लोबल वेल्थ मैनेजर की नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2026 खपत के स्तर में सुधार के मामले में भारत मजबूत आधार बनी रहेगी। इस दौरान भारत का घरेलू बाजार 10 प्रतिशत से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ेगा और इस तेज गति से वर्ष 2030 तक भारत का घरेलू बाजार लगभग 237 अरब डालर की ऊंचाई पर

सुहाना, लेकिन क्षणमंगुर

नवंबर 2025 में खासकर मैन्चूफैक्ट्रिंग सेक्टर की वजह से औद्योगिक क्षेत्र में भारत का अपेक्षाकृत मजबूत प्रदर्शन एक निरंतर रुझान की शुरुआत होने के बजाय ज्यादातर एक अचानक से हुई अच्छी बात है। नवंबर में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 6.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जो 25 महीनों में सबसे तेज विकास दर है। इसके तहत, मैन्चूफैक्ट्रिंग सेक्टर में आठ फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले 25 महीनों में सबसे तेज बढ़ोतरी थी। अक्टूबर 2025 में विकास दर धीमी होकर 14 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाने के मद्देनजर, देखने में यह बात खासतौर पर बेहद शानदार और हौसला बढ़ाने वाली लगेगी। हालांकि, विकास में यह उछाल ज्यादातर मौसमी और कुछ खास वजहों से आई थी। अर्थात्स्त्रियों के मुताबिक, विकास को सबसे ज्यादा बढ़ावा त्योहारी मौसम के बाद विक्रेताओं द्वारा अपने स्टॉक को फिर से भरने से मिला। दूसरी वजह यह है कि सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती का समय त्योहारी मौसम के साथ रखा। मांग में इस अस्थायी बढ़ोतरी से स्टॉक के स्तर और कम हो गए होंगे, जिन्हें फिर से भरने की जरूरत पड़ी। दरअसल, उपभोक्ता टिकाऊ एवं गैर-टिकाऊ वस्तुओं के क्षेत्र में नवंबर में वृद्धि हुई, जो बढ़कर क्रमशः 10.3 फीसदी और 7.3 फीसद हो गई, जो क्रमशः 12 महीने और 25 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। नवंबर में जिस तीसरे कारक ने काम किया, वह है अस्वाम्य रूप से लंबे मानसून के चलते दो महीनों की गिरावट के बाद खनन सेक्टर का वापस पत्थरी पर लौटना। नवंबर 2025 में खनन सेक्टर में 5.4 फीसदी की अच्छी-खासी वृद्धि देखी गई। ये सभी विकास में तेजी आने की जायज वजहें तो हैं, लेकिन टिकाऊ नहीं हैं। बिजली और खनन क्षेत्र मौसम की अनिश्चितताओं से प्रभावित होंगे।

Social Media Corner

सब के हक में...

सामनाथ में वीर हमीरजी गोहिल को श्रद्धांजलि अर्पित की। वे बर्बरता और हिंसा के दौर में साहस और दृढ़ संकल्प के प्रतीक बनकर खड़े रहे। उनकी वीरता देशवासियों की स्मृति में युगो-युगो तक अंकित रहेगी। उनका साहस और पराक्रम बताता है कि भारतवर्ष की संस्कृति को किसी भी प्रकार के बल प्रयोग से कमजोर नहीं किया जा सकता।



(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक्स' पर पोस्ट)

राजस्थान को कांग्रेस की सरकार ने ठेका कर का पर्याय बना दिया था, वहां मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार नोकरीयों में पारदर्शिता लाकर युवाओं का भविष्य संवार रही है। जयपुर में राजस्थान पुलिस के नवनि्युक्त 8 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों को नियुक्ति-पत्र वितरित किए। प्रदेश में तीन नए कानूनों के लागू होने के बाद नियुक्त वे पुलिस कर्मी नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ सुशासन व जनसेवा को और भी गति देने वाले हैं। साथ ही, सूरु जिले के तननगर थाना को प्रदेश के नंबर 1 थाने के रूप में सम्मानित भी किया और खेले झंडिया के तहत १4 करोड़ से अधिक की राशि से निर्मित मल्टीपर्स इंडोर हॉल का लोकार्पण भी हुआ।



(गृह मंत्री अमित शाह का 'एक्स' पर पोस्ट)

झारखंड आंदोलन के महानायक, राज्य निर्माता, बाबा दिशोम गुरु स्व. शिवू सोरेन जी की जयंती पर शत-शत मनन। बाबा का संघर्ष, बाबा का महान जीवन, बाबा की शिक्षा और आदर्श सदियों तक जन्मानस को न्याय, स्वाभिमान और संघर्ष की राह पर प्रेरित करते रहेंगे। दिशोम गुरु शिवू सोरेन अमर रहें!



(हेमंत सोरेन का 'एक्स' पर पोस्ट)

Civil-military gap must be bridged

IN April 2006, the Chairman, Chiefs of Staff Committee, wrote a letter to Raksha Mantri (RM) Pranab Mukherjee, seeking his "...personal intervention for the appointment of a Service officer as a constituted member of the 6th Central Pay Commission (CPC)" and reminding him that "...a lack of Service representation was perhaps one of the main reasons for the dissatisfaction expressed by the Services post 5th CPC award..." While expressing agreement in principle, the RM regretted his inability to comply with this request. The recommendations of the 6th CPC initially evoked a positive response due to an overall salary hike, but this quickly soured as specific anomalies emerged that were seen as unjust to the military. In an unprecedented move, the three Service Chiefs delayed submission of revised salary bills, effectively deferring implementation to send a message to the government. The reaction to the 7th CPC was even more severe, with the Service Chiefs, in 2016, taking the extraordinary step of writing to the Prime Minister about holding the implementation in abeyance; they executed it only after "assurances at the highest level" that anomalies would be addressed. Civil-military dissonance has been an issue of long-standing concern in India, and it constitutes a major flaw in our national security matrix. The root of this problem lies in two convictions of the politician; firstly, that "civilian control" of the military can/should be exercised on its behalf by the bureaucracy, and secondly, that civil-military relations are a "zero-sum game" in which civilian control can be maintained/enhanced only by balancing and blunting the military's influence/prestige. An indicator is the progressive blurring of lines between the military and the Home Ministry-helmed 1.1 million-strong Central Armed Police Forces (CAPFs). Since relative seniority in the government hierarchy is based on a functionary's "basic pay", the easiest way of altering established relativities is by changing the pay structures. The best instrument to effect such changes is the decadal CPCs staffed by bureaucrats. This is how successive pay commissions, all of which have excluded military representation, have served to aggravate this civil-military asymmetry. Typical of the anomalies that have caused serious concern to the military leadership is a policy termed "Non-Functional Upgrade" (NFU), which guarantees civilians automatic higher pay entitlements, even without a merit or vacancy-based promotion. By according this unjustifiable benefit to the civilians and then to the CAPFs, but denying it to the military, the CPC not only depressed the latter's relative status but also dealt a blow to morale. This sense of systemic discrimination was further fuelled by other measures, including a drastic cut in pensions for soldiers disabled on duty and a system of "hardship allowances" that favoured civilians in peace areas over the military in combat zones. A dive into history is necessary in order to get to the root of these problems.

At the time of Independence, a hurried reorganisation of the imperial defence structure took place to suit the new republic's needs. During this turmoil, the military leadership remained blissfully ignorant of a significant development orchestrated by the civil services; the armed forces HQs, instead of being designated independent "departments" of the Ministry of Defence (MoD), were reduced to "attached offices" and made subaltern to the Department of Defence. This "act of commission" was to be followed by equally significant "acts of omission". The Constitution, vide Article 312, created two new "All-India Services" — the IAS and the IPS (to be joined later by the Indian Forest Service). Inherited from the empire was another category of bureaucracy, known as the Central Civil Services, consisting of 89 Group 'A' and 'B' services.

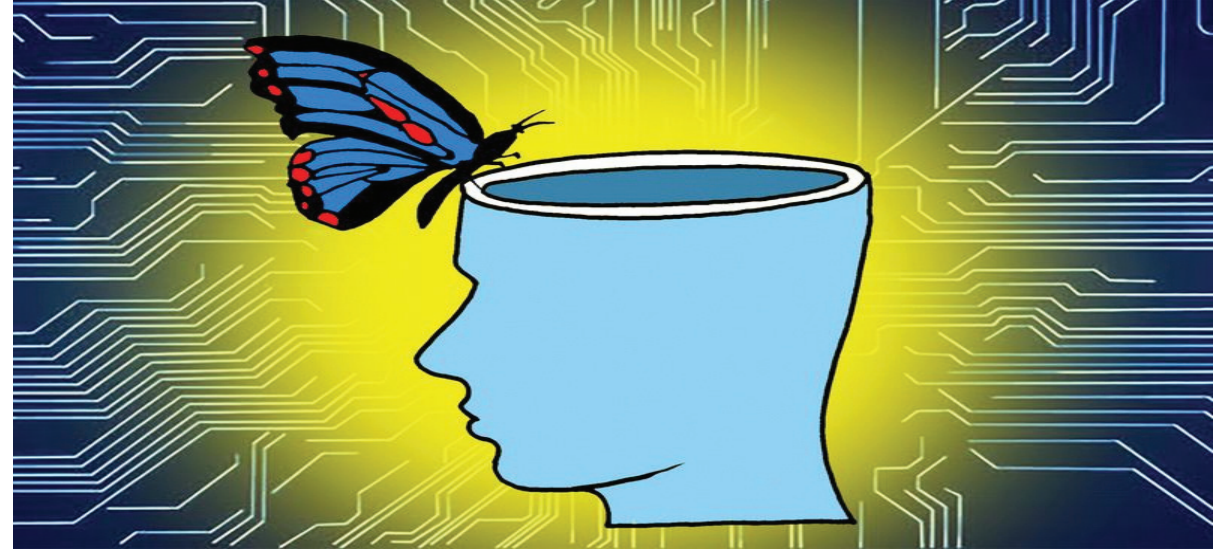
Fair use or free ride? AI copyright dilemma

India's copyright framework in AI must place the interests of creators ahead of an industry built on their work.

TOWARDS the end of 2025, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade published a working paper on 'Generative AI and copyright'. It is the report of an expert committee to examine the vexed question of copyright protection in the era of artificial intelligence, and its findings will most likely form the basis of India's policy on the subject in the near future. Generative AI products like ChatGPT, Gemini, Perplexity, etc, are large language models (LLMs) that generate content based on prompts given by users. For instance, one can provide a brief storyline and ask ChatGPT to write a short story in the style of RK Narayan or Premchand, and it would generate it. Similarly, Dall-E, Midjourney (and other similar text-to-image and text-to-video generation models) can make a painting on a given subject based on prompts to generate it in the style of, say, Jamini Roy or MF Husain or a short movie clip in Satyajit Ray's style. Such outputs from generative AI models are based on their training that uses data from a variety of types of sources (like novels of Narayan or paintings of Husain and others).

The data used for training AI models may fall in different categories — copyrighted, copyright-expired works and data in the public domain available for 'fair use'. Ever since technology firms launched commercial versions of generative AI products, the question of their use of copyrighted material, such as books, research papers, photographs, films and other forms of creative expression has become central to the AI debate. It has posed complex legal, ethical and moral questions. Another unresolved issue is the copyrightability and authorship of AI-generated outputs.

Governments and courts in many countries have been struggling to deal with this new phenomenon — data training of AI models. Technology companies worldwide, including in India, have argued that AI models do not violate copyright laws as they are not copying or plagiarising copyrighted books, photographs, etc, but using them only as segregated datasets to train algorithms using patterns, styles, structures in terms of statistical relationships to enable them to generate new content. This, they claim, amounts to the well-accepted dictum of 'fair use' of creative works. To argue that AI models are not 'copying' original works but only 'learning' from them does not hold water. This is because the process of training an AI system involves multiple steps, including copying and storage of data (original works), which, in effect, constitutes infringement. This, the AI industry says, can at most be considered a 'technical infringement', not a legal one. Rejecting the notion that no copyright licensing is required, and after studying various models being



discussed or implemented elsewhere in the world, the expert committee has recommended a hybrid framework for India. It has suggested a blanket licence to AI developers for the use of lawfully accessed copyright-protected works for training AI systems, provided the copyright holders are paid a royalty. But rightsholders will not have the option to withhold their works for use in the training of AI systems.

A centralised non-profit entity consisting of rightsholder organisations and designated by the government would be responsible for collecting the payments from AI developers. This entity would have copyright societies and industry organisations as its members, and these member-organisations would be responsible for passing on the royalties to individual creators. A certain percentage of the revenue generated from AI systems trained on copyrighted content would be payable as royalties, and the rates would be fixed by a government committee. Technology companies argue that regulating the use of creative works and enforcing new copyright laws to make licensing compulsory would hinder technological innovation. They demand complete exemption of text and data mining (TDM) from copyright laws to enable the training of AI models. The representative of the industry body, Nasscom, in the expert committee disagreed with its recommendations and gave a dissent note. Instead of a copyright system based on the revenue of AI models, it wants a layered system of using copyrighted materials. Nasscom has suggested that it was the responsibility of rightsholders to prevent the use of their publicly available work for TDM, and for this, they should be given an 'opt out'

option at the point of availability of their work. For content which is not publicly accessible, rightsholders should be able to protect their rights through contract or license terms. All this puts the onus on rightsholders to protect their work, which, under the present circumstances, is very difficult because copyright is being violated openly and protected material is available online illegally. Technology companies have already mined data from millions of books thus available online. The 'opt out' option also seems impractical in this scenario. In both cases, people who create new works (rightsholders) are going to be at the receiving end. The expert panel wants automatic availability of copyright-protected works for training of AI systems and will make it a legal certainty to help the AI industry, while denying copyright holders the right to opt out of the TDM system. On the other hand, the industry is not ready to accept the royalty-based system proposed by the government, but wants to make copyright holders responsible for protecting their works through means like an 'opt out' or individual contracts. Both types of regimes are unfair to the creators of original content. In any case, the creators will have to depend on policies and whims of the platforms (and other mediators) where their content is displayed. The AI companies have begun generating billions of dollars of business, and the volume is projected to grow. Yes, LLMs and other models are a result of technological innovation, but one that critically hinges on the digital theft of the work produced by millions of creative people around the globe over the decades. The copyright framework India is proposing must place the interests of creators ahead of those of the industry.

Congress fee: Hefty sum may put off some ticket aspirants

The Tribune Editorial: Alienating local workers by erecting financial barriers is nothing but a self-inflicted injury.

IT'S not uncommon for the Congress to charge application fee from ticket aspirants in poll-bound states. However, the party's decision to hike the fee to Rs 50,000 for the Assam Assembly elections has raised eyebrows. This is not a small amount, and it applies uniformly to all contenders for candidature. Moreover, refunds will reportedly be made only for those seats where the Congress will let its alliance partners contest. The ostensible rationale for the move is on familiar lines: a substantial application fee discourages non-serious aspirants. However, in a state with deep socio-economic disparities and intense intra-party competition, the "one-size-fits-all" approach seems to prioritise financial capacity over grassroots work. The party had given a concession to applicants from the reserved category in Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana and Haryana in recent years. The



Congress is certainly not the richest political party in India. Its fund balance of Rs 857 crore pales in comparison with the BJP's Rs 7,113 crore, as per data compiled by the

Election Commission for 2023-24. The saffron party continues to dominate political funding and donations even after the scrapping of the controversial electoral bonds scheme. The Congress, in contrast, does not have adequate money to smoothly run its state units and contest elections across the country.

However, the process of generating funds should not cause resentment among the party cadre. Alienating local workers by erecting financial barriers is nothing but a self-inflicted injury. The Congress needs to counter the BJP's claim that it has turned the ticket application process into a cash-driven exercise. Promising refunds across the board with a clear timeline can be helpful. The party should also go all out to refute the allegations that it allots tickets to the highest "bidders".

India's AI language leap

When people can dream and design in their mother tongue, innovation becomes truly bottom-up.

INDIA'S linguistic diversity, with 22 official languages and hundreds of dialects, has limited digital access for millions. A multilingual AI revolution now bridges this gap, turning access into empowerment and redefining inclusion as dignity. As India hosts the India AI Impact Summit 2026 on February 15-20 in New Delhi, it aims to build an AI ecosystem empowering every citizen through multilingual, multi-access models, embodying 'Sabka Saath, Sabka Vikas'. This ensures excluded groups participate in the digital future. By bridging the technology divide, India is unlocking its demographic dividend and entrepreneurial potential. When people can dream, design and deliver solutions in their own language, innovation becomes truly bottom-up, powered by the many, not the privileged few. AI is revolutionising education, healthcare and governance.

Yet, a critical gap remains. Most AI systems are trained primarily in English and a few global languages, sidelining billions whose native tongues are underrepresented. In India, barely 10% of the population is fluent in English. For the vast majority, digital access alone does not equal digital inclusion. True empowerment begins when people can engage with technology in their own language. India's approach is, therefore, a global model, showing how AI can democratise the digital economy.

India's multilingual AI revolution is anchored in BHASHINI, the government's flagship initiative under the National Language Translation Mission. BHASHINI powers voice, text and video translation across more than 35 Indian languages using over 1,600 AI models. Integrated into platforms such as CPGRAMS for grievance redress, My Aadhaar for digital identity and services like the IRCTC and NPCI's IVRS systems, it enables citizens to engage in their own



languages. Complementing this are homegrown large language models (LLMs). They include Sarvam-M by Sarvam.ai, the first indigenous LLM supporting 11 Indian languages plus English, built with over 500 billion parameters for nuanced, context-aware interactions and AI4Bharat's IndicTrans and IndicBERT, covering all 22 scheduled languages for seamless translation and dialogue. This ecosystem ensures that the promise of Digital India reaches the farmer, artisan, student and entrepreneur in every corner. As India's multilingual AI matures, it will enable millions of new creators, coders, innovators and

problem-solvers, fuelling a new wave of vernacular innovation that reflects the real voice of Bharat. Initiatives like Adi Vaani, the world's first AI-powered tribal language bridge, are preserving endangered languages and connecting indigenous communities to public services in their native tongues. Similarly, the Open Network for Digital Commerce (ONDC) uses BHASHINI to enable small businesses to create multilingual interfaces, expanding market access for MSMEs. These examples illustrate a universal truth — removing language barriers unlocks participation, fostering equitable economic and social empowerment.

The AI summit will focus on outcomes guided by three sutras: people, planet and progress. For multilingual AI, the summit recognises India's linguistic inclusion model as a global standard, emphasising the moral and technological responsibility to ensure AI speaks the full spectrum of languages. India stands not only as a technological leader but also as a champion of linguistic inclusion. Its message to the world is clear — to empower people, speak to them in their language. Only then can we truly unlock the nation's potential, harness its demographic dividend and shape a future where every citizen is not just connected, but truly included.

Q3 Earnings, Inflation Data And US Tariff Uncertainty Likely To Drive Sensex, Nifty Next Week

New Delhi.(Agency)

Indian stock markets are expected to remain volatile in the coming week as investors brace for a mix of key domestic and global triggers, including the start of the December quarter earnings season, the release of crucial inflation data, and continued uncertainty over US trade policies. Benchmark indices ended the past week on a weak note, extending their losing streak to five sessions, as caution ahead of corporate results and persistent foreign fund outflows kept sentiment subdued. The focus will now shift to how companies perform in the December quarter and whether macroeconomic numbers provide any relief to markets. The earnings season will kick off with major IT companies such as Tata Consultancy Services, HCL Technologies, Infosys, Wipro and Tech Mahindra announcing their Q3 results.

On the macro front, the coming week will be data-heavy, with India set to release CPI inflation, WPI inflation, trade balance figures and foreign exchange reserves data. These indicators will be crucial in assessing the health of the economy and shaping expectations around interest rates and policy outlook. Global cues will also remain in focus, especially developments related to US trade policy. The US Supreme Court is scheduled to hear and deliver decisions on key cases, including a challenge to President Donald Trump's sweeping global tariff measures. Any clarity or surprise ruling could influence global markets and, in turn, Indian equities. "Immediate resistance lies at 25,800, followed by 25,940 and 26,000, while support is placed at 25,600 and 25,450. A breakdown below 25,300 may intensify downside pressure," an expert said. On the daily timeframe, Nifty closed decisively below the crucial 25,800 resistance level -- reflecting a breakdown of an important supply zone and short-term bearish dominance," a market expert stated.

SEBI approval for NSE IPO soon; what it means for investors

New Delhi.(Agency)

The IPO of India's largest stock market index National Stock Exchange (NSE) seems to be coming soon. Market regulator SEBI may soon provide big relief for this much-awaited listing stuck for years. This is expected to end the long legal and regulatory uncertainty associated with the listing of NSE.

NSE IPO may get SEBI's green signal

SEBI Chairman Tuhin Kant Pandey said during a press conference in Chennai that a No-Objection Certificate (NOC) can be issued to the NSE soon. He indicated that this approval could possibly be obtained by the end of this month. After this, it will depend upon NSE how it plans to proceed with the process of IPO.

NSE IPO hurdles

NSE's IPO has been stuck for a long time due to the dark fibre case. In this case, there were allegations that between 2010 and 2014 some high-frequency traders were given preferential access to the co-location server through fast private connections, which gave them an unfair advantage in trading. In April 2019, SEBI had ordered the NSE to return the alleged illegal earnings of Rs 62.58 crore and banned some senior officers from performing market-related responsibilities. Apart from this, a penalty of Rs 7 crore was also imposed in 2022, which was later cancelled by the SAT. Against this, SEBI had moved to the Supreme Court, where the matter is still under consideration. Market infrastructure entities like stock exchanges, depositories, and clearing corporations are required to obtain NOC from SEBI before an IPO. This additional process is maintained because these institutions are considered the backbone of the country's financial system.

Space startup OrbitAid to showcase in-orbit refuelling tech for satellites

New Delhi.(Agency)

A Chennai-based space startup is all set to demonstrate its technology that would allow refuelling of satellites orbiting the earth, extending their lifespan and help address the challenges of space debris.

OrbitAid Aerospace is set to launch AyulSAT, a dedicated tanker-satellite, onboard the Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) on Monday to perform internal propellant transfer, power transfer and data transfer using its Standard Interface for Docking and Refuelling Port (SIDRP).

"We will first demonstrate transfer of fuel from one tank to another within the satellite," Sakthikumar Ramachandran, founder and CEO, OrbitAid, told PTL. Sakthikumar said AyulSAT will be India's first commercial docking and refuelling interface deployed in-orbit. We will soon have fuel stations in orbit that will enable life extension of satellites - both in low earth and geo synchronous orbits," he said. Sakthikumar said later this year OrbitAid will launch another satellite -- the designated chaser satellite -- that will dock with AyulSAT and demonstrate actual re-fuelling of satellites in orbit.

"AyulSAT will also now serve as the target satellite for our first Rendezvous Proximity Operations and Docking (RPOD) mission, with the launch of our chaser satellite by the end of 2026," Sakthikumar said. India will be the fourth country to demonstrate in-orbit re-fuelling of satellites and the AyulSAT mission will lay the foundation of the on-orbit economy - where satellites are serviced, refuelled, and sustained.

Budget 2026: Will old tax regime survive and should new regime get deductions

New Delhi.(Agency)

After offering meaningful relief to taxpayers in Budget 2025, expectations from the upcoming Union Budget appear more muted. Tax experts believe the government may now have limited room to offer further direct tax benefits, with the focus likely shifting towards simplification, fine-tuning existing changes, and improving tax administration rather than announcing fresh giveaways. Over the past few years, the government has steadily pushed the new tax regime as the default option while keeping the old regime alive for those with existing commitments and deductions. As Budget 2026 approaches, the key questions remain whether the old tax regime will continue and whether the new regime will finally see the introduction of deductions.

OLD TAX REGIME MAY NOT BE PHASED OUT IMMEDIATELY

Despite the government's clear preference for the new tax regime, experts say a

complete withdrawal of the old system may not happen just yet. Rohit Jain said official data shows a sizeable section of taxpayers still prefers the old structure. Official data shows a sizeable minority still prefers the legacy structure: for AY 2024-25, about 2.01 crore of 7.28 crore ITRs (28%) were filed under the old regime. "The old regime is still attractive for taxpayers who can substantiate material exemptions and deductions, especially HRA, home-loan interest on a self-occupied house, ss.80C, 80D, 80E, 80G etc. Given that 28% are still preferring old regime, immediate phase-out seems unlikely," said Jain. This suggests that while the government may continue nudging taxpayers towards the new regime, it may be cautious about removing the old option too quickly, especially for salaried individuals who rely on long-standing deductions.

LIMITED SCOPE FOR FRESH TAX RELIEF



When it comes to direct tax relief in Budget 2026, experts do not expect changes to income tax slabs or major exemptions.

SR Patnaik, Partner (head - taxation), Cyril Amarchand Mangaldas said the government has already extended significant benefits in the previous budget. "The budget for the previous year granted significant benefits to the taxpayers and hence, it is unlikely that there would be any significant tax benefits from a tax slab perspective." However, he added that the government could still look at targeted measures. "It is possible for the

Government to bring certain changes to further incentivise the tax paying population, especially to help them in owning residential property and possible also to facilitate their participation in the public market." This points to selective incentives rather than broad-based relief, keeping fiscal constraints in mind.

NEW REGIME LIKELY TO BE FINE-TUNED

On the gap between the old and new tax regimes, Patnaik said the coexistence of the two systems was never meant to be permanent. "The two separate tax regimes were kept for a temporary period so that people with existing obligations do not get adversely impacted by the budgetary changes and it is expected that the old tax regime shall be buried in the near future." For Budget 2026, however, expectations remain modest. According to him, taxpayers should not expect major announcements.

Will PF Stop Growing After You Quit A Job Latest EPFO Rules Explained

According to the latest rules followed by the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO), a PF account does not stop earning interest immediately after you leave a job.

New Delhi.(Agency)

A common concern among salaried employees is whether their Provident Fund (PF) balance continues to earn interest after they leave a job. With frequent job switches, layoffs, or career breaks becoming more common, many employees worry that their hard-earned PF savings may stop growing once they are no longer employed. According to the latest rules followed by the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO), a PF account does not stop earning interest immediately after you leave a job. In fact, your PF balance continues to earn interest even if there are no fresh contributions, provided certain conditions are met.

As per EPFO norms, a PF account earns interest until the account holder reaches the age of 58, which is

considered the retirement age under EPF rules. This means that even if an employee quits a job, remains unemployed, or takes a long career break, the PF balance will keep earning interest up to this age.

This clarification is important because many employees still believe that PF interest stops after three years of inactivity. That understanding comes from older interpretations of EPF rules, which have since been clarified. The EPFO has stated that the "three-year limit" does not apply as long as the member has not reached 58 years of age.

What Happens After 58

Once a PF member turns 58, the account is classified as inactive. At this stage, interest stops accruing, and the employee is expected to withdraw the PF amount or shift to pension benefits

where applicable. Keeping money idle in a PF account beyond this age does not generate any additional returns.

Tax Implications You Should Know

While interest continues to accrue, there can be tax implications if the PF remains unclaimed for a long period after retirement. If the account is not closed and no withdrawal is made, the interest earned after retirement may become taxable under income tax rules.

Why Transferring PF Is Still Important

Although interest continues after leaving a job, experts advise employees to transfer their PF account when switching employers. This ensures accurate record-keeping, prevents account fragmentation, and helps avoid delays or errors during final withdrawal.

Pre-Budget Meeting Positive And Constructive: States' Representatives

New Delhi.(Agency)

Chief Ministers, Deputy Chief Ministers and Finance Ministers from several states on Saturday described the pre-budget consultation meeting with Union Finance Minister Nirmala Sitharaman as a constructive platform to present their states' financial needs and development priorities ahead of the Union Budget. Goa Chief Minister Pramod Sawant said his government raised state-specific issues during the meeting and requested the continuation of Central Sector Schemes that have been running for the past five years. Uttar Pradesh Finance Minister Suresh Kumar Khanna said suggestions were invited from all states and UP presented proposals aimed at moving towards becoming an "Uttam Pradesh." "Every state expressed its desire to strengthen its financial position and accelerate growth,"

khanna stated. Telangana Deputy Chief Minister Mallu Bhatti Vikramarka said his state highlighted the challenges faced by states and sought more funds for key sectors such as education,



health and irrigation. "These sectors are crucial for long-term development and public welfare," Vikramarka stated. West Bengal Finance Minister Chandrima Bhattacharya said all ministers spoke on behalf of their states and placed their concerns before the Centre. "West Bengal requested that it should not be treated unfairly and

sought the release of nearly Rs 1.97 lakh crore in pending dues, explaining in detail the sectors to which these dues belong," she stated.

Jharkhand Finance Minister Radha

Krishna Kishor said Jharkhand had raised concerns about financial constraints and delays in receiving central funds. "Under a central scheme, the state has to bear a major share of the cost despite limited resources," he pointed out. He also alleged that central agencies are often misused in states where the ruling party at the Centre is not in power. Punjab Finance Minister Harpal Singh Cheema said Punjab suffered heavy economic losses due to border tensions and floods this year. He said a relief package of Rs 16 crore was announced earlier but has not yet been received, and the issue was raised again during the meeting.

absence of positive developments on the trade talks. Some negative comments from the US commerce secretary gave the impression that the trade agreement will be further delayed," he noted. This impacted the market sentiments and FIIs continued selling by increasing the volume of selling in the last two trading days.

The total FII selling (cash market) through January 9 stood at Rs 11,784 crore. The market sentiments have turned weak that despite DII buying of Rs 17,900 crore in January through 9, Nifty drifted down by 618 points in the week ending January 9.

The sell-off last week was broad-based, with cyclical and policy-sensitive sectors bearing the brunt of the correction. Energy, metals, and realty stocks emerged as the top laggards, weighed down by concerns over global trade disruptions, commodity demand uncertainty, and risk-off positioning. Banking stocks also declined, with Bank Nifty underperforming the broader market amid cautious sentiment and persistent FII selling, said Ajit Mishra - SVP, Research, Religare Broking Ltd. In the current environment of heightened volatility and global uncertainty, a cautious and disciplined approach is advisable.

Who says we can't be flexible: India eyes new markets with US trade deal limbo

Negotiations are underway with the EU, the EAEU, Mexico, Chile and the South American Mercosur trade bloc, either for new deals or to expand existing agreements.

New Delhi.(Agency)

India is aggressively seeking trade deals to open markets for exporters and soften the blow of steep US tariffs, as efforts to secure an agreement with Washington remain elusive. Relations between Washington and New Delhi plummeted in August after President Donald Trump raised tariffs to 50 percent, a blow that threatens job losses and hurts India's ambition of becoming a manufacturing and export powerhouse. That pressure, experts say, has pushed New Delhi into a rapid diversification drive beyond its biggest market.

India signed or operationalised four trade agreements last year, including a major pact with Britain -- the fastest pace of

dealmaking it has seen in years -- and is now eyeing fresh deals. Negotiations are underway with the European Union, the Eurasian Economic Union, Mexico, Chile and the South American Mercosur trade bloc, either for new deals or to expand existing agreements. If successful, India would have trade arrangements with "almost every major economy", said Ajay Srivastava, from the New Delhi-based Global Trade Research Initiative (GTRI).

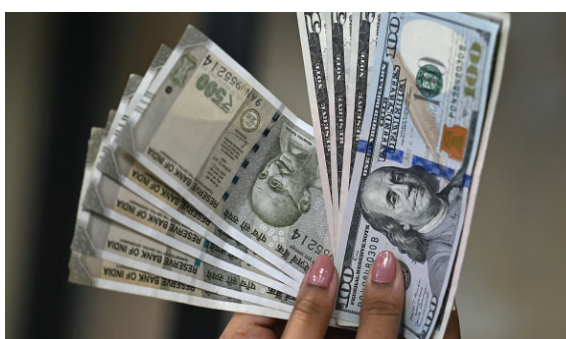
Srivastava said 2025 was "one of the most active years" for trade agreements, which he said aimed to "spread risk" rather than to pivot from Washington.

'Expand its destinations'

Washington's punishing tariffs aimed at stopping India's purchases of Russian oil -- which it says finances Moscow's invasion of Ukraine -- have driven New Delhi's desire to grow other markets.

"The strategy was a reaction, as I read it, to what Trump did," trade economist Biswajit Dhar told AFP. "This has now become an imperative for India to

actually expand its destinations." Major deals will help labour-intensive sectors hurt by tariffs. India's apparel export promotion council projects that the UK trade deal could help double garment exports to Britain over the next three



years. European Commission President Ursula von der Leyen, expected to visit New Delhi later in January, has said it would be the "largest deal of this kind anywhere in the world." Although the two sides missed a deadline to conclude talks by the end of 2025 -- reportedly over disputes related to steel and auto exports -- Indian negotiators remain optimistic.

German Chancellor Friedrich Merz will visit India and meet Prime Minister Narendra Modi on Monday, holding talks on "intensifying cooperation in trade and investment", Modi's office said in a statement.

Smaller agreements also matter

Trade between Oman and India totalled less than \$11 billion last financial year, but a December deal with Muscat offers "a gateway to the broader Middle East and Africa markets", and a template for a wider "Gulf engagement strategy", analysts at Nomura suggested.

And while a free trade agreement (FTA) with New Zealand added

little to Indian export growth, it secured \$20 billion in foreign investment, increased visa access and showed Washington that New Delhi is willing to compromise.

"The New Zealand FTA makes concessions on agricultural produce like apples, even though farmers here may have concerns," said an Indian commerce ministry official, who declined to be identified.

Delhi Assembly issues notices to 3 top Punjab Police officers over FIR against Kapil Mishra, others

The notices have been issued to Punjab's director general of Police (DGP), Special DGP (Cyber Cell) of Punjab and the Jalandhar Police Commissioner, Speaker Vijender Gupta told media persons.

New Delhi.(Agency)
The Delhi Assembly on Saturday issued notices to three Punjab Police officers, asking them to reply within 48 hours after an FIR was lodged in Jalandhar against Law Minister Kapil Mishra for allegedly sharing a doctored video of the Assembly proceedings in the Capital. The notices have been issued to Punjab's director general of Police (DGP), Special DGP (Cyber Cell) of Punjab and the Jalandhar Police Commissioner, Speaker Vijender Gupta told media persons. The Jalandhar Police Commissionerate had on Friday registered booked Mishra for allegedly uploading and circulating a doctored video, in which Leader of Opposition Atishi is allegedly seen insulting Guru Tegh Bahadur in the Assembly on Tuesday after a debate on a programme held last November to mark the 350th martyrdom day of the ninth Sikh Guru. A day later, Mishra had shared the video from his X account. According to the notices issued by the Delhi

Assembly Secretariat, the video has been referred for forensic examination and to the Committee of Privileges. The Assembly also asked for all the related documents and the forensic report, based on which Punjab Police claimed that the video was "doctored", Gupta said. "The matter is of extremely serious and constitutional importance and is directly linked to the dignity, authority, and privileges of the House. The issue is not confined to any individual or political party," he added. Gupta said that any recording of proceedings inside the House is the exclusive property of the Assembly and does not belong to any political party, individual, or external agency. "Misuse of the property of the House in this manner, and registration of an FIR against a minister on the basis of such material, is not only unfortunate but also extremely serious and condemnable," he added.

He questioned on what basis and under what authority the FIR in this matter was registered by Punjab Police. "The role of the Jalandhar Police commissioner in the entire episode is



highly questionable and appears prima facie to be a clear case of breach of privilege of the House. A direct case of privilege violation is therefore made out against him and the House will consider it seriously," Gupta said. Further, he pointed out that describing the

official recording of the House as "tampered" or "doctored" amounts to a direct attack on the dignity of the Assembly. "This is not merely a false allegation but appears to be a well-planned conspiracy aimed at undermining the prestige of the House and maligning constitutional institutions... Anyone found directly or indirectly involved in this conspiracy will face the strictest possible action by the House," Gupta said. The BJP MLAs have demanded cancellation of Atishi's Assembly membership for allegedly "insulting" the Sikh Guru. "She (Atishi) was asked to simply offer a brief apology, but she refused to do so; otherwise, the matter would have ended there itself," Gupta said. The AAP, meanwhile, demanded Mishra's Assembly membership to be revoked. "The AAP is firm in demanding the immediate termination of BJP Minister Kapil Mishra's membership over the 'beadbi' of Sikh Guru Sahibs," it said.

Double Trouble For Delhi: 'Poor' AQI, Yellow Alert For Dense Fog, Cold Wave

New Delhi.(Agency)
The India Meteorological Department (IMD) has issued a yellow alert for dense fog and warned of a cold wave in Delhi-NCR for Sunday and Monday, cautioning that weather conditions are likely to worsen over the next two days amid a sharp drop in temperatures. The national capital recorded its coldest morning of the ongoing winter on Saturday, with the minimum temperature at Safdarjung falling to 4.2 degrees Celsius, the lowest January reading in the last three years, according to IMD data. Daytime conditions also remained chilly, with the maximum temperature settling below normal at 19.7 degrees Celsius, adding to the prolonged winter discomfort across the city. With temperatures dipping sharply across several parts of Delhi, the weather department has also forecast moderate to dense fog during the morning hours, which is expected to significantly reduce visibility and further aggravate cold conditions. As per IMD norms, cold wave conditions are declared when minimum temperatures drop between 4.5 and 6.4 degrees Celsius below normal, depending on local climatology. Palam and Ayanagar recorded minimum temperatures of 4.5 degrees Celsius, while Lodi Road registered 4.7 degrees Celsius, and the Ridge area reported 5.3 degrees Celsius. Maximum temperatures across various weather stations also remained suppressed, ranging from 17.2 degrees Celsius at Palam to around 19 degrees Celsius at Safdarjung and Ayanagar. On Friday, the minimum temperature was recorded at 4.6 degrees Celsius. As the cold wave deepens, air quality has deteriorated further due to unfavourable meteorological conditions. Cold and calm winds have restricted the dispersion of pollutants, allowing pollution levels to accumulate over the city.

Infrastructure, education & transport in Delhi get boost in revised budget estimate

Officials said the move reflects a focus on building assets rather than routine spending.

New Delhi.(Agency)
The Delhi government has increased capital expenditure from Rs 28,115 crore to Rs 30,248 crore in the revised estimate for the 2025-26 fiscal to pump in more money into infrastructure, transport, education and civic services, but the budget size will be retained at Rs 1 lakh crore. The Delhi Assembly on Friday approved more funds for roads, metro projects, public transport, municipal bodies and power subsidies. Officials said the move reflects a focus on building assets rather than routine spending. A senior official said, "The revised budget aims to deliver visible improvements on the ground in mobility, public services and education." Allocation for transport, including roads and bridges, has been increased from Rs 12,952 crore to Rs 16,024 crore, a rise budget share from 13% to 16%. Funding for DMRC has been increased by Rs 2,117 crore, taking the total to Rs 5,046.66 crore. The DTC has got Rs 653 crore more, raising the allocation to Rs 3,433 crore. The MCD has received Rs 11,428 crore, an increase of Rs 1,031 crore, to support sanitation, road repairs, garbage collection and civic works. Loans to DJB has been increased to Rs 3,500 crore. "The funds will strengthen water supply and sewer networks," an official said. The electricity subsidy for domestic consumers has been raised to Rs 4,000 crore. Allocation for education sector has gone up from Rs 19,291 crore to Rs 20,702 crore. Funds for the purchase of flats and land for universities have risen by Rs 862 crore to Rs 1,362 crore. Housing and urban development allocation has increased to Rs 11,754 crore. The state's share under the Yamuna Action Plan has been increased by Rs 180 crore to Rs 280 crore. The funds will support river cleaning and sewage treatment projects. An additional Rs 100 crore has been earmarked for completion of Barapulla Phase-III corridor.

Delhi Govt writes to Centre seeking 3,300 e-buses to strengthen green public transport

New Delhi.(Agency)
Delhi may soon see an addition of over 3,000 buses to its green public transport fleet as the government steps up measures to curb vehicular pollution. The Delhi government, said officials, has sent a proposal to the Centre's Convergence Energy Services Limited (CESL), seeking an immediate procurement of 3,300 low-floor, air-conditioned electric buses. The Centre had set up CESL in 2020 with an objective to support the ambition of net-zero carbon emission by 2070. A high-level meeting was recently chaired by Chief Minister Rekha Gupta with CESL in this regard where a decision was reached to increase the city's bus allocation under the PM E-DRIVE Scheme

(Phase-2), said officials. According to the CM's Office, the government aims to ensure that the Capital can soon boast to have one of the largest and cleanest electric bus networks in



the world. The PM E-DRIVE Scheme is an initiative of the Union Ministry of Heavy Industries to accelerate the adoption of electric vehicles (EVs) by providing financial incentives with an aim to improve air quality.

Under the scheme, the Centre also helps the states in strengthening the charging stations and installation of fast chargers. After reassessing the bus requirements, according to the CMO, a demand has been placed for buses of different sizes to ensure connectivity from narrow streets to major arterial roads. Under this proposal, the government has sought 500 buses of 7 metres to serve narrow streets and provide last-mile connectivity to residents, 2,330 buses of 9 metres to operate on smaller roads as feeder services, and 500 buses of 12 metres to be deployed on main routes and heavily congested corridors. The new buses, the CMO said, will curb the public dependence on private vehicles and lead to a significant reduction in harmful emissions.

Not passing the buck, but BJP inherited water supply issues from AAP: Minister Parvesh Verma

New Delhi.(Agency)
Issues like contaminated water, pipeline leakages and irregular water supply in the national capital are not recent, but the result of years of neglect, Water Minister Parvesh Verma said on Friday, in apparent reference to the previous AAP government. Making this assertion in the assembly, he also said these chronic problems arose due to indecision and delay by the previous governments. The minister presented a detailed and fact-based statement in the Legislative Assembly, stating that the city government and Delhi Jal Board, with the support of the central government, is committed to ensure clean, equitable and

continuous (24x7) water supply to every household in Delhi. However, he said the current government inherited a dilapidated and severely neglected water infrastructure. "We did not create these problems, but we inherited them. The difference is that we are not running away from responsibility. We are

delivering solutions," he said. Addressing the House, Parvesh highlighted that out of Delhi's 16,000 km water pipeline network over 5,200 km pipelines are more than 30 years old and around 2,700 km pipelines are 20-30 years old. As a result, the city has been facing frequent leakages, pipeline bursts, contamination risks and Non-Revenue Water (NRW) losses of up to 55 percent. "When pipelines are 30 years old, it is not water that flows - problems do," he said. The minister informed that the Chandrawal and Wazirabad water reform projects, proposed as early as 2011, remained stalled for years due to the indecision, repeated tender cancellations and conflicts with funding agencies under the previous government.



NMRC Executive Director removed after calendar features his photos

New Delhi.(Agency)
The Noida Authority on Friday removed Noida Metro Rail Corporation (NMRC) Executive Director Mahendra Prasad, appointing Krishna Karunesh, the Authority's Additional Chief Executive Officer (CEO), in his place. On Saturday, The Indian Express reported that the official 2026 calendar of NMRC featured Prasad's photographs on the page for July, which also happened to be the month of his birthday. In the first photograph, Prasad - also the Officer on Special Duty in Noida Authority - can be seen walking in a corridor and in the second, addressing an event. A 2014-batch IAS officer, his birthday happens to fall on July 5. Prasad had said on Friday that

there was "nothing personal, nothing commercial" in the calendar. He had added that it was all in the government interest and not personal. "It's not as if I have printed anyone's photo who does not hold an official post," he had said. In a letter dated January 9, the Authority said, "In the immediate interest of the Authority's work, Shri Krishna Karunesh, Additional Chief Executive Officer, Noida, is nominated as the Executive Director, Noida Metro Rail Corporation, in place of Shri Mahendra Prasad, Officer on Special Duty, Noida, with immediate effect." As per the letter, the "said order was issued with the approval of the Chief Executive Officer,



Noida and the Managing Director, Noida Metro Rail Corporation Limited", Lokesh M, whose photographs also featured in the NMRC calendar. The calendar carried two photographs of Lokesh M, a 2005-batch IAS officer, for the

month of April. His birthday falls on April 3. In one photograph, the officer can be seen playing the sitar and in the other, addressing an event. Lokesh M had told The Indian Express on Friday that his photographs had been used

without his permission. He had also said that he had issued a "show-cause notice" to the officials concerned as soon as he came to know about the matter. The photograph was taken when he played Vande Mataram on the stage at Noida Authority's Independence Day celebration, he had added. However, in a purported photograph taken recently, Lokesh M could be seen posing with the calendar that featured his photographs, while other officials clapped. Though he did not respond to calls and messages on Saturday, an official said, "The show-cause notice was issued on the day the CEO learnt about the photographs. We are confirming when it was issued."

Four AAP MLAs out for rest of Delhi Assembly winter session

New Delhi.(Agency)
Speaker Vijender Gupta on Friday suspended four Aam Aadmi Party (AAP) MLAs for the remaining period of the ongoing Winter Session of the Delhi Assembly for "disrupting" House proceedings. In a statement, Gupta said, "due to the continuous disruption of the proceedings of the House and violation of its decorum, Opposition members (AAP) Som Dutt, Jarnail Singh, Sanjeev Jha and Kuldeep Kumar are suspended from the House for the rest of the Winter Session." The Vidhan Sabha Secretariat said that the decision of the Speaker was exercised strictly to preserve the authority, order, and dignity of the House and in full conformity with the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Delhi Legislative Assembly. The AAP MLAs demonstrated inside the Assembly complex demanding immediate resignation of minister Kapil Mishra for sharing a video related to alleged insult of Guru Tegh Bahadur by Leader of Opposition Atishi. Raising slogans outside the House, AAP leaders urged the Speaker to cancel the BJP minister's membership, with Chief Whip Sanjeev Jha saying the misuse of Guru Sahib's name to defame LoP Atishi was unacceptable. The demonstration was led by AAP MLAs Jarnail Singh and Kuldeep Kumar.

Meanwhile, Delhi BJP leaders and party workers also held a massive protest outside the AAP office against the alleged insult of Sikh Guru Guru Tegh Bahadur by Atishi. A large number of workers from the Delhi BJP's Sikh Cell also participated in the protest. BJP workers gathered at Windsor Place and marched towards the AAP office, raising slogans demanding Atishi's resignation and an apology from Arvind Kejriwal and Punjab CM Bhagwant Mann. Before reaching the office, Delhi Police stopped the BJP workers with heavy barricading near the Firozshah Road-Madhavrao Scindia Marg red light, announced their detention, and later released them after issuing a warning. Speaking on the matter, BJP National General Secretary Tarun Chugh said, "Atishi's conduct and statements in the Assembly reflect deep disrespect towards Sikh Gurus and Sikh traditions, and are also against constitutional dignity. Acting at the behest of Kejriwal, the repeated statements made by Punjab Chief Minister Bhagwant Mann in Punjab clearly prove that the AAP's approach towards Sikh faith has not been sensitive, but rather hostile. Such insults to Sikh religious symbols and traditions on constitutional platforms are not merely careless acts, but deliberate attempts to hurt the sentiments of Sikh community."

NEWS BOX

Greenland's harsh terrain and thin infrastructure block rare earth mining even as Trump seeks control

World. (Agency)

Greenland's harsh environment, lack of key infrastructure and difficult geology have so far prevented anyone from building a mine to extract the sought-after rare earth elements that many high-tech products require. Even if President Donald Trump prevails in his effort to take control of the arctic island, those challenges won't go away. Trump has prioritized breaking China's stranglehold on the global supply of rare earths ever since the world's number two economy sharply restricted who could buy them after the United States imposed widespread tariffs last spring. The Trump administration has invested hundreds of millions of dollars and even taken stakes in several companies. Now the president is again pitching the idea that wresting control of Greenland away from Denmark could solve the problem. "We are going to do something on Greenland whether they like it or not," Trump said Friday. But Greenland may not be able to produce rare earths for years — if ever. Some companies are trying anyway, but their efforts to unearth some of the 1.5 million tons of rare earths encased in rock in Greenland generally haven't advanced beyond the exploratory stage.

Trump's fascination with the island nation may be more about countering Russian and Chinese influence in the Arctic than securing any of the hard-to-pronounce elements like neodymium and terbium that are used to produce the high-powered magnets needed in electric vehicles, wind turbines, robots and fighter jets among other products. "The fixation on Greenland has always been more about geopolitical posturing — a military-strategic interest and stock-promotion narrative — than a realistic supply solution for the tech sector," said Tracy Hughes, founder and executive director of the Critical Minerals Institute. "The hype far outstrips the hard science and economics behind these critical minerals."

US launches new retaliatory strikes against ISIS in Syria after deadly ambush

WASHINGTON. (Agency)

US and allied forces carried out "large-scale" strikes against the Islamic State jihadist group in Syria on Saturday, the US military said, the latest response to an attack last month that killed three Americans.

US Central Command (CENTCOM), which oversees American military forces in the region, said multiple strikes "targeted ISIS throughout Syria," using an acronym for the jihadist group. CENTCOM's post on X did not give specifics on where they took place.

Grainy aerial video accompanying the post showed several separate explosions, apparently in rural areas. The strikes were part of Operation Hawkeye Strike, which was launched "in direct response to the deadly ISIS attack on US and Syrian forces in Palmyra," CENTCOM said. Two US soldiers and a US civilian interpreter were killed on December 13 after a lone gunman — whom Washington described as an IS militant — ambushed them in Palmyra, home to UNESCO-listed ancient ruins and once controlled by the jihadist group. Syria's interior ministry later said the gunman was a member of the security forces who had been set to be fired for extremism.

"We will never forget, and never relent," US Defense Secretary Pete Hegseth said Saturday in a post on X, replying to the CENTCOM statement.

The United States and Jordan carried out a round of strikes last month in response to the Palmyra attack, with CENTCOM saying at the time that "more than 70 targets" had been hit. The Syrian Observatory for Human Rights, a war monitor, later reported those strikes killed at least five IS members, including a cell leader.

Iran simmers: Over 100 killed as protests intensify; what military options is US considering

world. (Agency)

At least 116 people have been killed in violence linked to nationwide protests challenging Iran's theocratic leadership, which entered their second week on Sunday. The US-based Human Rights Activists News Agency reported that more than 2,600 people have also been arrested, citing verified reports.

With internet access restricted and phone lines cut across Iran, assessing the scale of the demonstrations has become increasingly difficult.

Iranian state television has focused on reporting casualties among security forces and projecting an image of control, while avoiding mention of dead protesters, whom it has increasingly described as "terrorists," as cited by AP.

The country's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has signaled an impending crackdown despite warnings from the United States. Iran's attorney general, Mohammad Movahedi Azad, also issued a warning that anyone taking part in the protests would be treated as an "enemy of God," a charge that carries the death penalty. A statement aired on state television said the designation would also apply to those who "helped rioters." "Prosecutors must carefully and without delay, by issuing indictments, prepare the grounds for the trial and decisive confrontation with those who, by betraying the nation and creating insecurity, seek foreign domination over the country," the statement read, as cited by AP. "Proceedings must be conducted without leniency, compassion or indulgence."

USA ready to help, says Donald Trump

Meanwhile, US president Donald Trump has been briefed on new options for possible military strikes against Iran as he weighs responding to Tehran's crackdown on protesters, according to multiple US officials.

What to know about the protests shaking Iran as government shuts down internet and phone networks

Protests began in late December with merchants in Tehran before spreading. While initially focused on economic issues, the demonstrations soon saw protesters chanting anti-

DUBAI. (Agency)

Nationwide protests in Iran sparked by the Islamic Republic's ailing economy are putting new pressure on its theocracy as it has shut down the internet and telephone networks. Tehran is still reeling from a 12-day war launched by Israel in June that saw the United States bomb nuclear sites in Iran. Economic pressure, which has intensified since September when the United Nations imposed sanctions on the country over its atomic program, has sent Iran's rial currency into a free fall, now trading at

over 1.4 million to \$1.

Meanwhile, Iran's self-described "Axis of Resistance" — a coalition of countries and militant groups backed by Tehran — has been decimated since the start of the Israel-Hamas war in 2023. A threat by US President Donald Trump warning Iran that if Tehran "violently kills peaceful protesters" the US "will come to their rescue," has taken on new meaning after American troops captured Venezuela's Nicolás Maduro, a longtime ally of Tehran. "We're watching it very closely," Trump has warned. "If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States." Here's what to know about the protests and the challenges facing Iran's government.

How widespread are the protests?

More than 570 protests have taken place across all of Iran's 31 provinces, the US-based Human Rights Activists News Agency reported early Sunday. The death toll had reached at least 116, it said, with more than 2,600 arrests. The group relies

on an activist network inside of Iran for its reporting and has been accurate in past unrest. Understanding the scale of the protests has been difficult. Iranian state



media has provided little information about the demonstrations. Online videos offer only brief, shaky glimpses of people in the streets or the sound of gunfire. Journalists in general in Iran also face limits on reporting such as requiring permission to travel around the country, as well as the threat of harassment or arrest by authorities. The internet shutdown has

further complicated the situation. But the protests do not appear to be stopping, even after Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei said "rioters must be put in their place."

Why the demonstrations started

The collapse of the rial has led to a widening economic crisis in Iran. Prices are up on meat, rice and other staples of the Iranian dinner table. The nation has been struggling with an annual inflation rate of some 40%. In December, Iran introduced a new pricing tier for its nationally subsidized gasoline, raising the price of some of the world's cheapest gas and further pressuring the population.

Tehran may seek steeper price increases in the future, as the government now will review prices every three months. Meanwhile, food prizes are expected to spike after Iran's Central Bank in recent days ended a preferential, subsidized dollar-rial exchange rate for all products except medicine and wheat.

Sham election': Myanmar holds second round of polling amid armed conflict

YANGON. (Agency)

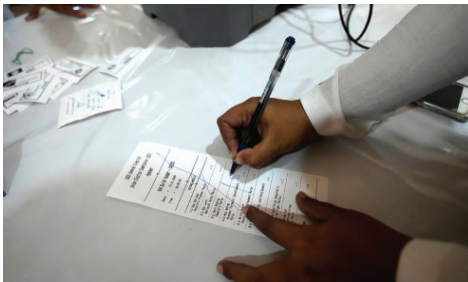
Myanmar resumed voting Sunday in the second round of its first general election in five years, expanding polling to additional townships, including some areas affected by the civil war between the military government and its armed opponents.

Polling stations opened at 6 am local time in 100 townships across the country, including parts of Sagaing, Magway, Mandalay, Bago and Tanintharyi regions, as well as Mon, Shan, Kachin, Kayah and Kayin states. Many of those areas have seen clashes in recent months or remain under heightened security, underscoring the risks surrounding the vote.

The election is being held in three phases due to armed conflicts. The first round took place on Dec. 28 in 102 of the country's total 330 townships, followed by the second phase on Sunday. A final round is scheduled for Jan. 25, though 65 townships will not take part because of fighting. Myanmar has a two-house national legislature, totaling 664 seats. The party with a combined

parliamentary majority can select the new president, who can name a Cabinet and form a new government. The military automatically receives 25% of seats in each house under the constitution.

Critics say the polls organized by the



military government are neither free nor fair and are an effort by the military to legitimize its rule after seizing power from the elected government of Aung San Suu Kyi in February 2021.

On Sunday morning, people in Yangon, the country's largest city, and Mandalay, the second-largest, were casting their ballots at high schools, government buildings and religious buildings. While more than 4,800

candidates from 57 parties are competing for seats in national and regional legislatures, only six parties are competing nationwide with the possibility of gaining political clout in parliament. The first phase left the military-backed Union Solidarity and Development Party, or USDP, in a dominant position, winning nearly 90% of those contested seats in that phase in Pyithu Hluttaw, the lower house of parliament. It also won a majority of seats in regional legislatures. The military government claimed more than 6 million people — about 52% of the more than 11 million eligible voters in the first phase of elections — cast ballots, calling the turnout a decisive success.

Suu Kyi, Myanmar's 80-year-old former leader, and her party aren't participating in the polls. She is serving a 27-year prison term on charges widely viewed as spurious and politically motivated. Her party, the National League for Democracy, was dissolved in 2023 after refusing to register under new military rules.

Anti-ICE protests across the US after shootings in Minneapolis and Portland, Oregon

World. (Agency)

Minnesota leaders urged protesters to remain peaceful Saturday as people gathered nationwide to decry the fatal shooting of a woman by a federal immigration officer in Minneapolis and the shooting of two protesters in Portland, Oregon. On Friday night, a protest outside a Minneapolis hotel that attracted about 1,000 people turned violent as demonstrators threw ice, snow and rocks at officers, Minneapolis Police Chief Brian O'Hara said during a news conference Saturday. One officer suffered minor injuries after being struck with a piece of ice, O'Hara said. Twenty-nine people were cited and released, he said. Minneapolis Mayor Jacob Frey stressed that while most protests have been peaceful, those who cause

damage to property or put others in danger will be arrested. He faulted "agitators that are trying to rile up large crowds." "This is what Donald Trump wants," Frey said of the president who has demanded massive immigration enforcement efforts in several U.S. cities. "He wants us to take the bait." Minnesota Gov. Tim Walz echoed that call for peaceful demonstrations. "Trump sent thousands of armed federal officers into our state, and it took just one day for them to kill someone," Walz posted on social media. "Now he wants nothing more than to see chaos distract from that horrific action. Don't give him what he wants." The demonstrations in cities and towns across the country come as the U.S. Department of Homeland Security

pushes forward in the Twin Cities with what it calls its biggest-ever immigration enforcement operation. Trump's administration has said both shootings were acts of self-defense against drivers who "weaponized" their vehicles to attack officers.

Steven Eubanks, 51, said he felt compelled to get out of his comfort zone and attend a protest in Durham, North Carolina, on Saturday because of what he called the "horrifying" killing of Renee Good in Minneapolis. Indivisible, a social movement organization that formed to resist the Trump administration, said hundreds of protests were scheduled in Texas, Kansas, New Mexico, Ohio, Florida and other states. Many were dubbed "ICE Out for Good" using the acronym for the federal agency.

Syria civil war: Kurdish fighters evacuated from Aleppo after days of violent clashes

WASHINGTON. (Agency)

Kurdish fighters were evacuated from a contested neighborhood in Syria's northern city of Aleppo, officials said early on Sunday, a move that could bring an end to several days of violent clashes with government forces.

State-run news agency SANA reported buses transported the last of the fighters from the Aleppo neighborhood of Sheikh Maqsood to northeastern Syria, which is under the control of the Kurdish-led Syrian Democratic Forces. "Through international mediation to halt the attacks and violations against our people in Aleppo, we have reached an understanding leading to a ceasefire and the safe evacuation of martyrs, the wounded, trapped civilians, and fighters from the Achrafieh and Sheikh Maqsood neighborhoods to northern and eastern Syria," SDF commander Mazloum Abdi said in a post on X. He called for "mediators to uphold their promises to stop the violations and work towards the safe return of the displaced to their homes." An

Associated Press journalist at the scene saw buses leaving Sunday and was told by officials that the transports carried 360 fighters. Other buses carrying civilians and detained fighters departed on Saturday.

Drone strikes are part of intense clashes

Syrian security forces deployed Saturday in Sheikh Maqsood after days of clashes with Kurdish fighters that killed and wounded dozens. During the day, several drone strikes were reported in Aleppo, Syria's largest city, leading authorities to stop civilian flights at Aleppo International Airport until further notice, state TV said.

On Saturday afternoon, an explosive drone hit the Aleppo Governorate building shortly after two Cabinet ministers and a local official held a news conference on the developments in the city. There was no immediate word on casualties.

Syria's state TV aired footage showing a drone exploding as it slammed into the building and blamed Kurdish fighters for

the attack. The SDF denied the reports, saying its fighters did not attack a civilian target. The fighting between the two sides is



the most intense since the fall of then-President Bashar Assad in December 2024. At least 22 people were killed in five days of clashes and more than 140,000 were displaced. US Special Envoy to Syria Tom Barrack held talks in Damascus Saturday with top officials, including President Ahmad al-Sharaa, and called on all parties to cease hostilities and return to dialogue. "Violence risks undermining the progress

achieved since the fall of the Assad regime and invites external interference that serves no party's interests," Barrack said in comments posted on X. "We urge all parties to exercise maximum restraint, immediately cease hostilities, and return to dialogue," he added, saying that fighting undermines the deal reached in March between the government and the Kurdish leadership. He said recent developments in Aleppo were "deeply concerning," and Washington's objective "remains a sovereign, unified Syria — at peace with itself and its

neighbors — where equality, justice, and opportunity are extended to all its people." Residents flee Kurdish-majority areas of Aleppo

Syria's state news agency SANA reported that two Kurdish fighters blew themselves up while surrounded by security forces without inflicting casualties, as gunfire was still heard in the neighborhood of Sheikh Maqsood around noon Saturday.

NEWS BOX

Varun Chakravarthy will be key for India in T20 World Cup: Sourav Ganguly

New Delhi. (Agency)

Former India captain Sourav Ganguly believes India's prospects of defending their T20 World Cup title at home will hinge significantly on how well Varun Chakravarthy performs in the tournament, underlining the importance of the team's spin-heavy bowling attack.

Ganguly, speaking briefly about India's preparations in an interaction with PTI, stressed that home conditions place an even greater premium on quality spin bowling, something he feels India are well-equipped with heading into the global event. "Yeah, nothing (home WC) gets bigger than that, and India is always my favourite team. They have a strong spin attack and if Chakravarthy is fit then it's good for India," Ganguly said, highlighting both the expectations and opportunities that come with hosting the tournament. India have indeed gone all-in on spin for the upcoming T20 World Cup, selecting a formidable quartet of Varun



Chakravarthy, Kuldeep Yadav, Axar Patel and Washington Sundar. With matches set to be played across India and Sri Lanka from February 7 to March 8, spin is expected to play a decisive role as surfaces wear and conditions slow down. Among them, Chakravarthy stands out as a key weapon. The mystery spinner has taken 51 wickets in 32 T20Is and arrives at the World Cup on the back of an impressive showing against South Africa, where he picked up six wickets in a five-match series. His ability to deceive batters in the middle overs makes him central to India's plans, especially in high-pressure knockout matches. As India gear up for their final T20I series before the World Cup, starting January 21 against familiar rivals New Zealand, Varun Chakravarthy's form has become one of the biggest talking points among fans and experts alike.

Rishabh Pant suffers painful series-ending blow during IND vs NZ training

NEW DELHI. (Agency)

India's preparations for the ODI series against New Zealand had already taken a hit on January 10 when Rishabh Pant was ruled out with an abdominal injury. A day later, on January 11, a video from India's Vadodara training session surfaced on social media, showing the exact moment Pant suffered the blow that ultimately ended his series before it began. The incident occurred during a routine net session ahead of the first ODI, when Pant suddenly felt discomfort in the right lateral side of his abdomen while batting. He was immediately attended to by the team's medical staff, and concerns over the injury prompted further examination. An MRI



scan was subsequently conducted, and after an online consultation with Dinshaw Pardiwala, Pant was diagnosed with a right-sided abdominal strain along with an internal oblique muscle tear. The findings confirmed that he would miss the entire three-match ODI series against New Zealand, which begins in Vadodara on January 11. Pant's absence is a significant setback for India, given his impact as a left-handed wicketkeeper-batter and his ability to change the tempo of an innings. Following a brief period of rest, he is set to report to the Centre of Excellence for further assessment and rehabilitation. With Pant unavailable, the selectors moved swiftly to name Dhruv Jurel as his replacement in the ODI squad on the morning of the 1st ODI. Jurel now has an opportunity to stake his claim in the middle of a busy white-ball phase for India.

IND vs NZ: Dhruv Jurel replaces injured Rishabh Pant, joins ODI team in Vadodara

India vs New Zealand: Dhruv Jurel has been added to India's ODI squad following Rishabh Pant's injury setback. The Uttar Pradesh wicketkeeper has joined the squad in Vadodara, the BCCI confirmed.

New Delhi. (Agency)

Dhruv Jurel has been added to India's one-day international squad for the upcoming three-match series against New Zealand, beginning January 11 in Vadodara, following Rishabh Pant's injury setback. The Board of Control for Cricket in India (BCCI) confirmed the development on matchday morning, stating that Jurel joined the Indian team in Vadodara on the eve of the series opener. As reported by India Today, Pant was ruled out after sustaining an abdominal injury during a training session, a blow to



India just days before the start of the series. Pant experienced sudden discomfort in his right lateral abdominal region while batting in the nets, prompting immediate medical evaluation. An MRI scan was conducted to determine the severity of the issue, after which a detailed consultation was held with orthopaedic specialist Dr Dinshaw Pardiwala. Medical assessments revealed a

right-sided strain along with an internal oblique muscle tear, ruling Pant out of the entire series. The 28-year-old wicketkeeper-batter will undergo a short period of rest before reporting to the Centre of Excellence for further assessment and rehabilitation. His absence forces the team management to recalibrate their plans ahead of the New Zealand series, where Pant was expected to

add depth and flexibility to India's middle order. Jurel's inclusion comes on the back of a prolific domestic season. The Uttar Pradesh wicketkeeper has been in outstanding form in the Vijay Hazare Trophy, scoring 558 runs in seven matches, including two centuries. Despite his strong performances, Jurel had earlier missed out on selection and remained on the sidelines during India's home series against South Africa in December. The injury to Pant, however, has reopened the door for the 23-year-old, who is regarded as one of the most promising wicketkeeper-batters in the domestic circuit. Whether Jurel will feature in the playing XI remains uncertain, with KL Rahul expected to be the first-choice wicketkeeper for the ODI series.

Pant's latest injury represents another interruption in an ODI career that has struggled to gain continuity in recent years. He last featured in a 50-over match during India's tour of Sri Lanka in August 2024. Although named in squads for the England series and the Champions Trophy earlier this year, Pant did not play a single match.

Unstoppable: Criminal lawyer Penav Mota defying odds to chase Paralympics dream

A criminal lawyer by trade and a long-distance runner by heart, Penav Mota looks to break down the barriers and represent India in the Paralympics soon.

NEW DELHI. (Agency)

"It pays to persevere. If you persevere for long enough, your dreams may just come true." Those were the words of China's Yang Yue to her daughter after winning gold in the F64 discus at the Paris Paralympics 2024 — a message that perfectly captures the essence of life as a para athlete. Perseverance is not optional; it is essential. That very principle has guided Penav Mota from a young age. After developing an eye-related condition in childhood, Penav lost vision in his left eye around the age of seven. Over time, his vision in the right eye also began to deteriorate. By the age of 15, he was

completely blind. But that never stopped him from chasing his dream of becoming an athlete and making a name for himself in sport. Penav began his sporting journey with chess as a child before moving into cricket.



Following his vision impairment, he explored blind cricket, swimming, cycling, and marathon running. It was in endurance disciplines — marathon running, cycling, and swimming — where he truly found his calling, and his achievements speak volumes. He proudly says he has completed 23 half marathons, two full marathons, one Pro Slam Run, one-hour and two-hour stadium runs, and BRM cycling events of 200 km and 300 km. Last year, Penav also competed in the Tata Steel World 25K

Kolkata, completing the race in the 25K category. Yet, beyond his accomplishments on the field, Penav continues to break barriers off it as well. A practising criminal lawyer based in Mumbai, the para athlete is determined to give back to his community. In 2024, he founded the Penav Mota Foundation with the aim of transforming the lives of the visually impaired through sport, wellness, and education.

Ahead of the Tata Mumbai Marathon on January 18, India Today caught up with the para athlete-cum-criminal lawyer to speak about his journey, ambitions of reaching the Paralympics, and his efforts to uplift the visually impaired sporting community.

THE START AND THE CHALLENGES

The beginning was never easy for Penav as a visually impaired athlete, despite his love for sports. His parents, naturally protective, initially restricted him to indoor activities. "I loved sports, but because of my poor vision, I wasn't allowed to play outdoor games like cricket. There was always a concern—'How will you play if you get hurt?' Because of this, my parents put me into chess, which is an indoor sport.

The Ashes was a spectacle. Why doesn't Test cricket in India feel the same

New Delhi. (Agency)

The sun had barely set on the 2025–26 Ashes, but the afterglow was felt six thousand miles away in India. Even as Australian and English fans celebrated a series that redefined "appointment viewing", Indian fans were left with a familiar, gnawing sense of envy. It was not just the cricket — though that was high-octane — it was the theatre of it. The Ashes felt like a cultural festival. It served as a powerful reminder of what Test cricket can look like when the game, the broadcast and the surrounding culture align in perfect harmony. Over five Tests played across Australia, more than 859,000 fans attended the matches, with an average crowd of nearly 48,000 per day — the highest daily average in Australian cricket history. The Melbourne Cricket Ground alone set a single-day attendance record of over 93,000 fans on Boxing Day.

Meanwhile, the iconic Sydney Cricket Ground hosted a cumulative 211,032 spectators for the final Test, breaking a long-standing attendance mark. In India,



the narrative is starkly different. While the Indian Premier League (IPL) is a neon-lit behemoth that swallows the calendar whole, Test cricket often feels like the neglected elder sibling — respected in

speeches, but poorly dressed and ignored in practice. "Cricket gyaan: what joy watching the fabulous Ashes TV coverage, every angle covered. Wonderful to see the crowds and little kids streaming into the Sydney ground after the game to catch a glimpse of their heroes while ensuring players get their moment in the sun. Players patiently signing autographs with no pushing and jostling. And the focus is always on the TEAM and not individuals. And yes, the coveted Ashes trophy given by a legend in Steve Waugh and not any official or sponsor. Not to forget that the Sydney Test is now the 'Pink Test' with part of the money going for breast cancer treatment through the McGrath Foundation. Much that @BCCI can learn from. There is much more to building a great cricket culture than just earning money guys! Agree?" wrote senior journalist Rajdeep Sardesai on X, triggering a wider debate.

Beyond the Ro-Ko madness: Stars hope to maximise ODI series to cut out noise

NEW DELHI. (Agency)

It was almost a year ago, around this time, that a lot of noise surrounded Virat Kohli and Rohit Sharma and their futures in Test cricket. A poor Border-Gavaskar Trophy had many calling for their heads, with some even urging the BCCI to look beyond the Indian greats and give youngsters a longer run. Before the England tour arrived, Rohit and Kohli decided that their time in whites was over. They chose to become one-format players, focusing solely on ODIs. Once again, the noise refused to die down, with many questioning how the duo could stay fit and motivated for the national team given the long breaks between assignments. The Australia white-ball tour was even touted as a possible swansong, with sections of fans believing the duo might not make it to the ODI World Cup in 2027. The signs appeared ominous when Rohit was removed as ODI captain and Shubman Gill was handed the leadership role. What followed, however, was an absolute masterclass from the

veterans. India lost the first two matches of the series, but the final game in Sydney served as a reminder of what Rohit and Kohli are capable of. The duo stitched together an unbeaten 168-run partnership, with Rohit scoring a brilliant century and Kohli returning to form with an unbeaten 74. It was vintage ODI batting from two players who had begun their international journeys almost at the same time. The caravan then moved to South Africa, and once again the spotlight was firmly on Kohli. Could he sustain his form? The response was swift and emphatic. Two centuries, a fifty, and 302 runs in three matches — there were no half-measures, just pure ODI batting within the framework of modern cricket. Then came another directive from the BCCI: play the Vijay Hazare Trophy. While this applied to all players, a section of fans felt it was indirectly aimed at the star duo. Once again, Rohit and Kohli let their bats do the talking for Mumbai and Delhi respectively. Rohit began with an explosive hundred off just



62 balls and finished with 155 from 94 deliveries. Kohli matched the intensity with 131 off 101 balls and followed it up with a fluent fifty. Their short stints ended with Rohit scoring 155 runs and Kohli amassing 208, leaving fans wanting more. To put the doubts into perspective, Kohli and Rohit

finished as India's highest run-getters in ODIs in 2025. Kohli scored 651 runs, while Rohit followed closely with 650. The duo also occupy the top two spots in the ICC ODI rankings, with Rohit at No. 1 and Kohli right behind him. So can they afford to take their foot off the pedal for one series? The answer is a clear no. Every match and every series is now a test as they march towards Mission 2027.

INDIA'S ODI SCHEDULE

India's next ODI assignment after the New Zealand series will be the England white-ball tour, with the 50-over matches beginning on July 11. This leaves a gap of nearly six months without international cricket for the star duo.

A poor showing in the New Zealand series would once again raise questions about their readiness for the World Cup next year, which will be played on fast, bouncy South African tracks. By then, both Kohli and Rohit will be approaching their forties.

FA Cup: Manchester City score 10 past Exeter City, Antoine Semenyo bags a debut goal



NEW DELHI. (Agency)

Manchester City marked the start of their FA Cup campaign with an extraordinary statement, tearing apart Exeter City 10-1 in a one-sided third-round clash at the Etihad Stadium.

Fielding a strong lineup, Manchester City were in complete control from the opening exchanges and effectively settled the contest before half-time. Teenager Max Alleyne opened the scoring by forcing the ball home from a corner, before Rodri doubled the lead with a powerful strike. Nathan Aké's effort made it three, and Exeter's misery deepened when Jack Fitzwater inadvertently turned the ball into his own net just before the interval.

City showed no signs of easing off after the break. Rico Lewis struck early in the second half, followed swiftly by a debut goal from Antoine Semenyo, who announced himself in emphatic fashion in sky blue. Tijjani Reijnders added a seventh with a curling finish from distance, as City's dominance stretched across every area of the pitch. Substitutes continued the rout late on, with Nico O'Reilly heading in an eighth and Ryan McAidoo marking his own debut with a well-taken ninth. Exeter briefly found a moment of pride through a fine George Birch finish, but City responded immediately, Lewis completing the scoring to take the hosts into double figures. The night belonged in large part to Semenyo. Signed from Bournemouth just days earlier, the Ghanaian forward capped his first appearance with a goal and an assist, underlining why City invested heavily in his arrival. His energy, movement and directness stood out even in a game overflowing with goals, earning him the man-of-the-match award. The result marked City's biggest win under Pep Guardiola and their heaviest FA Cup victory in decades, matching a 10-goal margin last seen in 1987. Guardiola himself watched from the stands due to a one-match touchline ban, with assistant Pep Lijnders overseeing proceedings. As City cruised into the fourth round, the scoreline served as both a warning to future opponents and a reminder of the squad's depth. For Exeter, it was a bruising evening, while for City, the FA Cup journey began in record-equaling, ruthless style.



Sunny Leone

Daniel Weber Step Out With Kids; Fans Calls Them 'Beautiful Family'

Whenever celebrities step out with their families, the vibe instantly turns wholesome and heartwarming, making such paparazzi moments a delight to watch. Living up to this, Sunny Leone was recently spotted by the paparazzi with her family, and the video was nothing short of adorable. Sunny, along with her husband Daniel Weber and their kids, Nisha, Noah and Asher, were seen arriving together for a screening. The clip perfectly captured their warm family bond and left fans smiling.

It's Family Time For Sunny!

The lovely family was spotted at a web series screening in Andheri, and they looked absolutely charming. Sunny opted for a brown top paired with khaki pants, while Daniel kept it casual in a black T-shirt and denims. The kids, however, stole the spotlight as all three looked effortlessly chic in stylish outfits.

In the video, the family was seen calmly posing for the paparazzi. Sunny was also spotted saying something to the kids as they wrapped up their poses, making for an adorable moment. The comments on the video were filled with praise for the family. A user wrote, "Great family and cute children." Another one added, "Beautiful family." Someone commented, "I miss her in Bollywood" "Oh...good to see the affection shown towards their adopted daughter," wrote another user. An individual remarked, "Looking so beautiful, Sunny Leone, love you."

Christmas Celebrations Done Right

While Sunny's New Year reel focused more on her professional achievements of 2025, the family's Christmas celebration was all about togetherness. Sunny shared a series of pictures from the festivities, where she can be seen posing with her family and friends amid beautiful Christmas decorations. One of the pictures also features Tejasswi Prakash posing with Nisha, Noah, and Asher.

The photo dump perfectly captured a warm, fun-filled family affair. The caption on her post read, "From our family to yours! Merry Christmas everyone! I hope you had a great one!" Influencer Anisha Dixit who was a part of the celebrations commented on the post, "Thank you, it was an amazing Christmas."



'My House Could Have Been Next': Daisy Shah Recounts Horrifying Fire Incident In Her Building



Actor Daisy Shah recently experienced a frightening fire incident in her neighbourhood. The actress recalled how the fire broke out after a spark from a sky shot used during a political rally went inside a neighbour's house. Recounting the scary encounter, Shah revealed that she keeps her house windows closed because she has a pet dog, but if the situation had been otherwise, her house could have also caught fire due to carelessness. While speaking to Mid-Day, the actress said, "Luckily, there were no human casualties. I'll put it that way, but my neighbour had pets, their cats escaped; however, their fishes and birds couldn't survive the fire."

"My house is 20 feet away from where the fire was. Yes, my house could have been the next target," Daisy added.

While talking about the traffic during office hours and how it delayed the emergency services from reaching on time, Shah said, "Considering it was office hours, and we do not have a dedicated lane for ambulances and fire engines, it took them about 30-35 minutes to reach."

"Our country's AQI has already gotten so bad. We don't need crackers. There is no proper place dedicated to bursting crackers. Abroad, they have specific spaces. We don't have such measures here," the actress added while calling bursting crackers a menace, and continued, "I am raising a question against the system, not against one political party. Each and every party should be held accountable."

Fire Breaks Out in Residential Building

A fire broke out in a 12-storey residential building in Mumbai's Bandra (East) area on Tuesday night. The fire on the 11th floor of the building was reported to the Mumbai Fire Brigade (MFB) at 8:54 pm, news agency PTI reported. The fire was confined to the 11th floor, and Fire Brigade personnel brought it under control within 10-15 minutes, according to officials.

Taking to her Instagram handle, Daisy Shah shared a video and strongly criticised the irresponsible behaviour that, according to her, led to the frightening incident.

'Where Is She Going?': Netizens Ask As Rashmika Mandanna Gets Spotted Amid Wedding Rumours



Rumours of Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda's wedding have been making headlines for a long time now. While the couple has neither confirmed nor denied the reports of their February wedding, Rashmika was recently spotted travelling solo, which left netizens wondering, 'Where is she going?' On Friday night, a video of the actress surfaced on social media in which she was seen arriving at the Mumbai airport.

She sported a brown top with black pants and kept her look casual. Rashmika was also seen smiling for the cameras as paparazzi followed her to the entrance gate. However, the actress did not say anything and chose to walk silently amid her wedding rumours.

Soon after the video of the actress surfaced on social media, one of the netizens rushed to the comments section and asked, 'Where is she going?'. It also remains unclear if Rashmika is travelling for some preparation regarding her wedding.

Recently, Rashmika and Vijay were also in Rome, celebrating the New Year. Even though the two stars did not mention that they were vacationing together, they shared photos from the same spots, which left netizens convinced that they were indeed together.

Reportedly, Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna got engaged privately in October 2025, surrounded by close family members. While the couple hasn't announced their engagement as of now, a report by Hindustan Times recently claimed that the wedding is scheduled for February 26, 2026, and will take place at a palace in Udaipur.

A source revealed that no celebrity guests will be invited and the event will be a private ceremony. "Rashmika and Vijay's wedding is planned at one of Udaipur's heritage palaces. Much like their engagement, the ceremony will be a close-knit affair with only their loved ones in attendance," the insider added.

Samantha Ruth Prabhu

And Raj Nidimoru Blush As They Attend FIRST Event Together After Getting Married

Samantha Ruth Prabhu and Raj Nidimoru made their first public appearance at an event together after their marriage. The couple, who got married on December 1, 2025, in an intimate ceremony, turned heads as they stepped out for an event. The pictures and videos now circulating on social media show them beaming with joy as they couldn't stop blushing.

In the video, Samantha looked absolutely stunning in a



beautiful white saree paired with minimal makeup. The actress tied her hair up in a half-clutch. Meanwhile, Raj looked dapper as he complemented his wife perfectly in a black T-shirt, pants, and a brown jacket. The couple's effortless coordination in their outfits made them look every bit the power couple they are. Raj and Samantha were seen standing close as they posed for the paparazzi. In the video, Samantha was seen holding Raj as they got clicked while attending an event together for the first

time after their marriage.

Inside Samantha and Raj's Love Story and Wedding

For those unaware, Samantha Ruth Prabhu and Raj Nidimoru had reportedly been in a relationship for several years before deciding to take the plunge. The duo is believed to have fallen in love during the shoot of Citadel: Honey Bunny.

Over the past few months, they were frequently spotted together at various locations and were seen celebrating festivals and personal milestones as a couple. The pair chose to keep their wedding ceremony low-key and private, with only around 30 guests in attendance.

Following the wedding, Samantha shared official pictures from the ceremony on her social media handles, offering fans a glimpse into their special day. The intimate celebration was widely appreciated by fans, who flooded the comments section with congratulatory messages.

On a related note, Samantha was previously married to actor Naga Chaitanya. The Ye Maaya Chesave co-stars tied the knot in 2017 after transitioning from friends to partners. However, the couple announced their separation in 2021 and later finalised their divorce. Following the split, Naga Chaitanya went on to date actor Sobhita Dhulipala, and the two got married in 2024.

